

NHRC issues notice to 5 States over missing person cases

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to the Chief Secretaries and Directors-General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, expressing concern over the growing number of missing persons reported in these States. The NHRC took cognisance of reports indicating that Bihar has recorded 12,000 to 14,000 missing persons cases annually since 2013; a significant proportion of them involving children. Reports suggest that only around two-thirds of the missing children have been traced. The NHRC has sought for steps already taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children.

NHRC steps in, seeks reports on missing children from 5 states

NARESH BISWANI

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report which highlighted the fact that a huge number of cases of missing persons are pending in Bihar, a majority of whom are children.

The media report states that between 12,000 and 14,000 cases of missing persons are registered every year in the state of Bihar since 2013. However, only two-thirds of the missing children have been found so far.

The NHRC has observed that "the matter is of serious concern to the Commission". The contents of the media report, if true, reveal serious violations of human rights.

Observed that "the matter is of serious concern to the Commission"

The Commission is also concerned about the fact that even after taking various measures to deal with the issue of missing persons, the number of such cases is increasing while only a few cases are being successfully solved."

According to the report, based on data provided by the National Crime Records Bureau (NCRB), it was observed that the highest numbers of human trafficking cases were registered in Odisha, Bihar, Telangana, and Maharashtra. Among

these states, Odisha reported the highest numbers of cases related to the trafficking of minor boys, followed by Bihar. In the case of trafficking of minor girls, the highest numbers of incidents were reported in Rajasthan.

The media report, which was released on March 9, 2026, also raised concerns that some of these missing children could be engaged in illegal activities such as begging, child labour, prostitution, etc.

To address this issue, the NHRC has directed the Chief Secretaries of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, along with their respective Directors General of Police, to provide information on this issue within two weeks.

NHRC takes cognisance of Gurugram wall collapse

GURUGRAM, MARCH 13

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of reports regarding the collapse of a wall at an under-construction site near Bilaspur in Gurugram that claimed the lives of at least seven workers and left three others injured on March 9.

According to reports, the incident occurred at a construction site where a sewage treatment plant (STP) was being built for an upcoming residential project. Several labourers were working at the site when a wall suddenly collapsed, trapping workers under the debris. Authorities initially feared that around 10 work-

Seeks report from government within two weeks

ers might have been trapped following the incident.

Taking serious note of the tragedy, the NHRC observed that if the reports were accurate, the incident raised serious concerns regarding the human rights of the victims, particularly in relation to workplace safety and the protection of labourers.

The Commission has issued notices to the Haryana Chief Secretary and the Gurugram Police Commissioner, directing

them to submit a detailed report within two weeks.

The report has been sought on the current condition of the injured workers, progress in the investigation, and the compensation or relief provided to the families of the deceased as well as to the injured labourers.

According to media reports published on March 10, several rescue agencies were engaged in search and rescue operations after the collapse. Teams from the police, civil defence, fire department and the State Disaster Response Force (SDRF) jointly carried out operations to locate and rescue workers trapped under the rubble.

Probe into cannon use from historic fort

A probe has been ordered by the National Human Rights Commission (NHRC), and notice has been issued to multiple central and state government officials over a complaint pertaining to "unsafe and unauthorised" use of cannon on the Archaeological Survey of India (ASI)-protected historic Raisen Fort in central MP's Raisen district. In the complaint it has been alleged that unauthorised and unsafe use of the cannon was taking place daily at the historic fort and vibrations and noise from firing the cannon were damaging the ancient structure. The complainant alleged that videos on social media showed individuals making provocative statements.

उत्तम नगर हत्याकांड: एनएचआरसी ने जिला मजिस्ट्रेट को जारी किया नोटिस

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने होली के दिन यहाँ उत्तम नगर में झड़प में हुई 26 वर्षीय एक युवक की हत्या के संबंध में पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और नगर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है और उनसे दो सप्ताह के भीतर कार्वाई रिपोर्ट मांगी है। मामले की कार्यवाही के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अधिकांशों को चार मार्च की इस घटना की पूरी तरह से और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने तरुण की मौत के सिलसिले में दो नाबालिगों को पकड़ा है और 14 वयस्कों को

गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के त्योहार के दौरान पड़ोसियों के दो गुटों के बीच झड़प के दौरान तरुण की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 10 मार्च को अपनी कार्यवाही में कहा कि शिकायत मिलने के बाद उसने इस मामले का संज्ञान लिया है। शिकायतकर्ता प्रकाश ने आरोप लगाया है, उत्तम नगर में होली के त्योहार के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के एक समूह ने तरुण पर बेरहमी से हमला किया, उसे पीट-पीटकर मार डाला। होली के दौरान कथित तौर पर पानी के मामूली छींटे पड़ने के कारण दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ तथा फिर यह घटना हुई।

सिग्नेचर ग्लोबल हादसे में मानवाधिकार आयोग ने सरकार व सीपी से मांगा जवाब

गुरुग्राम, 13 मार्च (ह्र)

गांव सिधरावली के पास निर्माणाधीन सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिट्टी ढहने से सात श्रमिकों की मौत और चार के घायल होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने राज्य सरकार और गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया गया या नहीं।

हादसा सोमवार देर रात हुआ। खुदाई के दौरान मिट्टी के ढहने से मजदूर मलबे में दब गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमों ने कई घंटों तक राहत कार्य कर शव

और घायलों को बाहर निकाला। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कहा कि यह सीधे मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण मजदूरों की जान गई। आयोग ने प्रशासन से घायल मजदूरों के स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट और मृतकों के परिजनों व घायलों को दिया गया मुआवजा पेश करने को कहा है। युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप जैलदार ने कहा कि यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि भवन नहर जैसी संरचना में बना था, ऊपर की ईंटों की दीवार नीचे गिर गई और मजदूर दब



घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य का फाइनल फोटो। -हप

गए। हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को देर से मिली क्योंकि बिल्डर ने घायलों को राजस्थान के अस्पताल भेजा।

जेलदार ने मांग की है कि शहर

और जिले के सभी निर्माण स्थलों पर श्रम विभाग और पुलिस नियमित निरीक्षण करें, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके और कानून का पालन सुनिश्चित हो।

मणिपुर की युवती की पिटाई मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस

जासं, दक्षिणी दिल्ली: मालवीय नगर में आठ मार्च को मणिपुर की युवती की कथित पिटाई के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मित्र संग टहल रही युवती पर कुछ लड़कों ने टिप्पणी कर मारपीट की थी। पुलिस ने चार नाबालिगों को पकड़ा था। आयोग के मुताबिक घटना पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर रिपोर्ट देने को कहा है।

उत्तम नगर हत्याकांड पर एनएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर और डीएम को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने होली के दिन उत्तम नगर में झड़प में हुई 26 वर्षीय युवक तरुण की हत्या के संबंध में पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) व पुलिस को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मामले की कार्यवाही के अनुसार एनएचआरसी ने अधिकारियों को चार मार्च की इस घटना की 'पूरी तरह से और निष्पक्ष जांच' करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने तरुण की मौत के सिलसिले में दो नाबालिगों और 14 वयस्कों को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के त्योहार के दौरान पड़ोसियों के दो गुटों के बीच झड़प के दौरान तरुण की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 10 मार्च को अपनी कार्यवाही में कहा कि शिकायत मिलने के बाद मामले का संज्ञान लिया है। शिकायतकर्ता प्रकाश ने आरोप लगाया है कि उत्तम नगर में होली के त्योहार के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के एक समूह ने तरुण पर बेरहमी से हमला किया, उसे पीट-पीटकर मार डाला। शिकायत के अनुसार होली के दौरान कथित तौर पर पानी के मामूली छींटे पड़ने के कारण 'दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ व फिर यह घटना हुई। आरोप है कि तरुण के परिजनो द्वारा माफी मांग लिए जाने के बाद

भी करीब 15-20 लोगों ने उस पर उस वक़्त हमला कर दिया, जब तरुण दोपहिया वाहन से घर लौट रहा था। शिकायत में कहा गया है कि हमलावरों ने कथित तौर पर ईंटों, पत्थरों और लोहे की छड़ों से पीटा,



● आयोग ने अधिकारियों को घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करने के लिए निर्देश

जिससे तरुण को गंभीर चोटें आईं। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है और मामले की उचित जांच, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने, पीड़ित के परिवार की सुरक्षा तथा शोकाकुल परिवार को पर्याप्त

मुआवजा दिलाने की मांग की है। आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया 'पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन' जान पड़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अगुवाई वाली उसकी एक पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले का संज्ञान लिया है। कार्यवाही में निर्देश दिया जाता है कि वह पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करे और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने का निर्देश दे।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगा सख्त एक्शन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दूरका डिस्ट्रिक्ट के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन गुब्बारा फेंकने के विवाद में हुई युवक तरुण की हत्या के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान करते हुए आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ऐसे वीडियो और पोस्ट डाले जा रहे थे, जिनमें गलत और भ्रामक जानकारी दी जा रही थी। इससे माहौल बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की निगरानी शुरू कर दी थी। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि उत्तम नगर हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग गलत जानकारी और भड़काऊ पोस्ट साझा कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना और भ्रामक जानकारी साझा करना कानूनन अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक वीडियो से 37 लाख जुटाने का खुलासा

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोशल मीडिया पर एक मार्मिक वीडियो पोस्ट कर लोगों से आर्थिक मदद की अपील की गई थी। इस वीडियो के साथ एक व्यूआर कोड भी साझा किया गया था, जिसके माध्यम से लोगों से पैसे भेजने के लिए कहा गया था पुलिस जांच में सामने आया कि 10 मार्च को यह वीडियो पोस्ट किया गया था और मात्र दो दिनों के भीतर ही संबंधित बैंक खाते में करीब 37 लाख रुपये जमा हो गए। पुलिस ने व्यूआर कोड से जुड़े बैंक खाते की जानकारी जुटाई और खाते की क्रेडिट और डेबिट सुविधा को ब्लॉक करा दिया।

एक्स-इंस्टाग्राम पर 22 अकाउंट चिन्हित

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर 14 अकाउंट की पहचान की गई है, जिनसे लगातार भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे। वहीं इंस्टाग्राम पर भी आठ ऐसे अकाउंट सामने आए हैं। पुलिस ने इन सभी अकाउंट की जानकारी संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को भेज दी है और उनसे आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का अनुरोध किया गया है।

सात श्रमिकों की मौत मामले में आयोग ने लिया संज्ञान

गुरुग्राम: सिधरावली में मिट्टी धंसने से सात श्रमिकों की मौत मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव व गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। (जासं)

NHRC takes cognisance of G'gram wall collapse

GURUGRAM, MARCH 13

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of reports regarding the collapse of a wall at an under-construction site near Bilaspur in Gurugram that claimed the lives of at least seven workers and left three others injured on March 9.

According to reports, the incident occurred at a construction site where a sewage treatment plant (STP) was being built for an upcoming residential project. Several labourers were working at the site when a wall suddenly collapsed, trapping workers under the debris. Authorities initially feared that around 10 workers might have been trapped following the incident.

Taking serious note of the tragedy, the NHRC observed that if the reports were accurate, the incident raised serious concerns regarding the human rights of the victims, particularly in relation to workplace safety and the protection of labourers.

The Commission has issued notices to the Haryana Chief Secretary and the Gurugram Police Commissioner, directing

them to submit a detailed report within two weeks.

The report has been sought on the current condition of the injured workers, progress in the investigation, and the compensation or relief provided to the families of the deceased as well as to the injured labourers. — TNS

NHRC seeks report from govt on missing persons

POST NEWS NETWORK

Bhubaneswar, March 13: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of reports, highlighting the rising number of missing persons, and poor recovery rates in several states, including Odisha, and has sought a detailed report from the state government within two weeks.

According to reports cited by the commission, data from the National Crime Records Bureau (NCRB) indicates that Odisha records one of the highest numbers of human trafficking cases in the country. The state reportedly tops the list for trafficking of minor boys, followed by Bihar. In cases involving trafficking of minor girls, Rajasthan has reported the highest number.

Taking serious note of the issue, the NHRC has issued notices to the chief secretaries and directors general of police of five states—Odisha, Bihar, Telangana, Maharashtra and Rajasthan—seeking detailed information on the situation.

The commission has asked the Odisha government to submit a comprehensive report



outlining the steps taken or proposed to tackle the increasing number of missing persons, particularly children. The report is also expected to explain measures being implemented to prevent trafficking and improve the tracing and rescue of missing individuals.

The NHRC observed that if the reports are accurate, the situation raises serious concerns about human rights violations. Many missing children are suspected to have been forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities by trafficking networks.

The commission has also di-

rected NCRB to provide the latest statistical data on missing persons and trafficking cases in the five states within the same two-week timeframe.

Human rights activists have long expressed concern over trafficking routes operating through eastern India, with Odisha often cited as a vulnerable region due to migration, poverty and cross-state trafficking networks. The latest action by the NHRC is expected to put renewed focus on the issue and prompt stronger coordination between law-enforcement agencies and child protection authorities.

NHRC issues notice to 5 States over missing person cases

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to the Chief Secretaries and Directors-General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, expressing concern over the growing number of missing persons reported in these States. The NHRC took cognisance of reports indicating that Bihar has recorded 12,000 to 14,000 missing persons cases annually since 2013; a significant proportion of them involving children. Reports suggest that only around two-thirds of the missing children have been traced. The NHRC has sought for steps already taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children.

NHRC takes cognisance of 'increasing' number of missing people, 'poor' record in tracing them

Press Trust of India
New Delhi, Mar 13

The NHRC on Friday said it has taken cognisance of a report that of the 12,000-14,000 missing persons' cases registered every year in Bihar since 2013, many of whom are children, "barely two-thirds of the missing children were recovered".

The data of the National Crime Records Bureau (NCRB) is believed to suggest that the maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar,

Telangana and Maharashtra, it said.

Therefore, the rights panel has issued notices to the chief secretaries and director generals of police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, seeking a detailed report in two weeks, the rights panel said.

Odisha tops the list of the maximum number of minor boys trafficking cases followed by Bihar, the statement said.

In the trafficking of minor girls, Rajasthan apparently

has registered the maximum cases.

According to a media report carried on March 9, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities, it said.

The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of human rights violations of the victims. It has also taken note of the reported concern that despite various mea-

sures taken by states, "the number of missing persons is increasing", and only "a few of them are traced", the statement said.

The report is expected to include the steps taken or proposed to be taken to deal with the increasing number of missing persons, especially children, the rights panel said.

Further, the Commission has sought the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these states within two weeks.

NHRC issues notice to 5 States over missing person cases

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to the Chief Secretaries and Directors-General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, expressing concern over the growing number of missing persons reported in these States. The NHRC took cognisance of reports indicating that Bihar has recorded 12,000 to 14,000 missing persons cases annually since 2013; a significant proportion of them involving children. Reports suggest that only around two-thirds of the missing children have been traced. The NHRC has sought for steps already taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children.

NHRC issues notice to 5 States over missing person cases

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to the Chief Secretaries and Directors-General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, expressing concern over the growing number of missing persons reported in these States. The NHRC took cognisance of reports indicating that Bihar has recorded 12,000 to 14,000 missing persons cases annually since 2013; a significant proportion of them involving children. Reports suggest that only around two-thirds of the missing children have been traced. The NHRC has sought for steps already taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children.

Hindalco hosts National Human Rights Conference in Bhubaneswar

EXPRESS NEWS SERVICE

@ Bhubaneswar

HINDALCO Industries Limited on Friday organised a national-level Human Rights Sensitization Conference in Bhubaneswar, bringing together policymakers, jurists, corporate leaders and civil society representatives from across the country for deliberations on rights-based development and ethical governance.

The conference, held at the Mayfair Convention in collaboration with Human Rights Front, aimed to bring together diverse stakeholders to build a common and deeper understanding of human rights standards across industries.

The inaugural session featured member of the National

Human Rights Commission (NHRC) Dr Justice Bidyut Ranjan Sarangi, former chairperson of the Odisha Human Rights Commission Justice Bimala Prasad Das, former member of OHRC Asim Amitabh Das, vice-chancellor of Maa Manikeswari University, Kalahandi Nibedita Nath, chief human resources officer of Hindalco Industries Limited Samik Basu, senior vice-president VR Shankar and president HR TM Prakash.

Delivering the keynote address, Basu said, "At Hindalco, respect for human rights is fundamental to how we operate. Anchored in our values of Integrity, Commitment and Seamlessness, we remain dedicated to building safe, inclusive and responsible workplaces. Safety and well-being

lie at the core of our people philosophy, and this conference reinforces our belief that sustainable growth is only possible when dignity and care for every individual guide every decision," he said.

The conference featured three thematic panel discussions addressing key human rights issues. The first panel discussion focused on 'Rights-Based Development: Advancing Equity, Inclusion and Institutional Accountability'.

The second examined 'Corporate Responsibility and ESG', focusing on ethical business practices and compliance with national and global human rights standards.

The final panel addressed 'Labour Codes and Human Rights: Balancing Ease of Doing Business with Worker Protection'.



NHRC issues notice to 5 States over missing person cases

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to the Chief Secretaries and Directors-General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, expressing concern over the growing number of missing persons reported in these States. The NHRC took cognisance of reports indicating that Bihar has recorded 12,000 to 14,000 missing persons cases annually since 2013; a significant proportion of them involving children. Reports suggest that only around two-thirds of the missing children have been traced. The NHRC has sought for steps already taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children.



NHRC issues notice to 5 States over missing person cases

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to the Chief Secretaries and Directors-General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, expressing concern over the growing number of missing persons reported in these States. The NHRC took cognisance of reports indicating that Bihar has recorded 12,000 to 14,000 missing persons cases annually since 2013; a significant proportion of them involving children. Reports suggest that only around two-thirds of the missing children have been traced. The NHRC has sought for steps already taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children.



NHRC issues notice to 5 States over missing person cases

The National Human Rights Commission on Friday issued notices to the Chief Secretaries and Directors-General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, expressing concern over the growing number of missing persons reported in these States. The NHRC took cognisance of reports indicating that Bihar has recorded 12,000 to 14,000 missing persons cases annually since 2013; a significant proportion of them involving children. Reports suggest that only around two-thirds of the missing children have been traced. The NHRC has sought for steps already taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children.

मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा



मिट्टी
ढहने से
मौत

गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एसटीपी की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से सात श्रमिकों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। शुक्रवार को आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। दो सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए गए।

सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कॉलोनी में सोमवार देर रात निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की खुदाई करने

इलाज, आर्थिक सहायता की जानकारी मांगी

आयोग ने अपनी नोटिस में तीन मुख्य जानकारियां मांगी हैं। घायल मजदूरों के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति और उन्हें दिया जा रहा उपचार। पुलिस और प्रशासनिक जांच का विवरण और दोषियों पर की गई कार्रवाई। मृतक मजदूरों के परिजनों और घायलों को दी गई आर्थिक सहायता या मुआवजे का ब्योरा भी मांगा गया है।

के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई। इस मलबे की चपेट में आने से 11 मजदूर दब गए थे। सात की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार घायल हो गए थे। एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करते हुए कहा है कि यदि खबरें सही हैं तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। आयोग

दो लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डर कंपनी, ठेकेदार सहित अन्य छह लोगों पर बिलासपुर थाने में केस दर्ज किया था। प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जेल भेजा चुका है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को मृतक श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 20-20 लाख के चेक दिए थे।

ने यह संकेत दिया है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से निर्दोष मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ठेकेदार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस तरह के हादसों में जान जाना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है।

मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा



गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एसटीपी की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से सात श्रमिकों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। शुक्रवार को आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। दो सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए गए।

इलाज, आर्थिक सहायता की जानकारी मांगी

आयोग ने अपनी नोटिस में तीन मुख्य जानकारियां मांगी हैं। घायल मजदूरों के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति और उन्हें दिया जा रहा उपचार। पुलिस और प्रशासनिक जांच का विवरण और दोषियों पर की गई कार्रवाई। मृतक मजदूरों के परिजनों और घायलों को दी गई आर्थिक सहायता या मुआवजे का ब्योरा भी मांगा गया है।

सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कॉलोनी में सोमवार देर रात निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की खुदाई करने

दो लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डर कंपनी, टेकेदार सहित अन्य छह लोगों पर बिलासपुर थाने में केस दर्ज किया था। प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जेल भेजा चुका है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को मृतक श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 20-20 लाख के चेक दिए थे।

के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई। इस मलबे की चपेट में आने से 11 मजदूर दब गए थे। सात की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार घायल हो गए थे।

लापता लोगों व मानव तस्करी पर पांच राज्यों को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली, 13 मार्च। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या और उन्हें ढूँढने में प्रशासन के निराशाजनक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मानव तस्करी को लेकर बिहार समेत पांच राज्यों से आयोग ने मांगी रिपोर्ट

पटना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार समेत पांच राज्यों को नोटिस भेजा है। बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान और महाराष्ट्र में लापता लोगों और मानव तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर नोटिस दिया गया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर इन राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि बिहार में 2013 से हर साल 12000 से 14000 लोग लापता हो रहे हैं।

गुरुग्राम में खुदाई के दौरान हुआ था हादसा सात मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर को नोटिस

भास्कर न्यूज़ | गुरुग्राम

सिंधरावली स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स प्रोजेक्ट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की खुदाई के दौरान हुए हादसे में सात मजदूरों की मौत के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने शुकवार को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सोमवार देर रात उस समय हुआ जब निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में एसटीपी की खुदाई का काम चल रहा था। अचानक मिट्टी ढहकर मजदूरों पर गिर गई। मलबे में दबने से 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन

चला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्विवल डिफेंस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए कहा है कि यदि खबरें सही हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला हो सकता है। आयोग ने प्रशासन से घायलों की स्वास्थ्य स्थिति, अब तक हुई पुलिस व प्रशासनिक जांच और दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है। पुलिस ने बिल्डर कंपनी, ठेकेदार सहित छह लोगों के खिलाफ बिलासपुर थाने में मामला दर्ज किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर व स्ट्रक्चरल इंजीनियर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है।



Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/human-trafficking-odisha-among-5-states-to-get-nhrc-notice/articleshow/129563907.cms>

Human trafficking: Odisha among 5 states to get NHRC notice

TNN | Mar 14, 2026, 12.44 AM IST

Bhubaneswar: Taking a suo motu cognisance of media reports highlighting a rise in trafficking and missing person cases, National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the chief secretaries and directors general of police of five states, including Odisha — which topped the list for trafficking from 2021 to 2023 — seeking a detailed report within two weeks.

According to National Crime Records Bureau (NCRB) data of 2023 — released on Sept 30 last year — the highest number of human trafficking cases was reported in Odisha, followed by Bihar, Telangana, Maharashtra and Rajasthan. Odisha recorded the highest number of human trafficking cases — especially involving minor boys — in the country in 2023, when a total of 1,305 people were trafficked from the state.

Odisha topped the human trafficking chart for three consecutive years, with 1,120 trafficking victims in 2022 and 1,475 in 2021.

In cases involving minor girls, Rajasthan reported the highest number.

The NHRC, in a release on Friday said the report should include steps taken and proposed to address the rising number of missing people, particularly children. It also sought the latest NCRB statistical data on the status of missing people in these states.

“Despite various measures taken by states, the number of missing persons is increasing and only a few of them are traced,” the commission said, adding there is suspicion that many of the trafficked children are being forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.



Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/transgender-board-nhrc-seeks-report/articleshow/129563727.cms>

Transgender board: NHRC seeks report

TNN | Mar 14, 2026, 12.30 AM IST

Patna: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint alleging systemic discrimination by the Bihar govt against the transgender community following the state's failure to operationalise the Bihar State Transgender Welfare Board.

Acting vice chairperson of the board Rajan Singh said, "Despite the board's formation six months ago, the body remains non-functional and leaves the community without administrative representation."

According to the NHRC case file, "The complainant alleges that the Bihar government formed the Bihar State Transgender Welfare Board on Aug 8, 2025, but since then, members have not been given office space and their post has been declared 'without salary', leading to discrimination."

The file further notes that as a result of these conditions, "many transgender community complaints remain unregistered" and police protection and support during district-level public hearings are also not provided. "The NHRC informed the Bihar State Human Rights Commission regarding this issue," Singh said. "Additionally, the Bihar govt and the principal secretary of the social welfare department were asked to give a report to the NHRC on the matter within six weeks," he added.

The transgender community in Bihar, which has an estimated population of over two lakh, remains largely unregistered.

Singh accused the govt of forming the board prior to elections to secure the support of the vote bank. "The state govt is discriminating against us," Singh said. "The social welfare department declared our positions unpaid. If we aren't provided with a salary or an office, how are we expected to work? This is unconstitutional," he added.

Source: <https://odishatv.in/odisha/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-rising-missing-persons-cases-odisha-among-states-flagged-for-high-human-trafficking-incidents-11211375>

NHRC takes suo motu cognizance of rising missing persons cases; Odisha among states flagged for high human trafficking incidents

The NHRC of India has taken suo motu cognizance of reports highlighting a rising number of missing persons and the poor rate of tracing them, with Odisha emerging as one of the states with a high number of human trafficking cases.

Vikash Sharma

14 Mar 2026 08:26 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognizance of reports highlighting a rising number of missing persons and the poor rate of tracing them, with Odisha emerging as one of the states with a high number of human trafficking cases. The Commission has issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police (DGPs) of Odisha, Bihar, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, seeking a detailed report within two weeks on the issue.

According to the NHRC, the action follows a media report published on March 9, 2026, which highlighted concerns regarding the increasing number of missing persons cases in several states. The report cited National Crime Records Bureau (NCRB) data indicating that the highest number of human trafficking cases have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra.

Among these, Odisha tops the list in cases related to the trafficking of minor boys, followed by Bihar. In the case of trafficking of minor girls, Rajasthan has recorded the highest number of cases, according to the report.

The NHRC also referred to data indicating that Bihar has been registering between 12,000 and 14,000 missing person cases every year since 2013, many of them involving children. However, barely two-thirds of the missing children in the state have reportedly been traced. The Commission noted that if the contents of the report are accurate, the situation raises serious concerns about potential human rights violations involving vulnerable victims, particularly children.

The Commission has further observed that despite various measures taken by state governments, the number of missing persons continues to rise while the tracing rate remains inadequate. It has therefore sought detailed reports from the five states on the steps taken or proposed to address the increasing number of missing persons, especially children.

In addition, the NHRC has asked the National Crime Records Bureau to provide the latest statistical data on the status of missing persons in Odisha, Bihar, Telangana, Maharashtra and Rajasthan within two weeks.

The media report cited by the Commission also raised concerns that many missing children are suspected to be forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities, highlighting the seriousness of the issue and the need for stronger preventive and investigative measures.

The NHRC stated that it will review the responses from the states and the NCRB once the reports are submitted.



Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/forced-to-carry-a-body-nhrc-demands-report-on-shocking-incident-of-man-carrying-stillborn-child-questions-raised-over-hospital-negligence/amp_articleshow/129563170.cms

Forced to carry a body: NHRC demands report on shocking incident of man carrying stillborn child; Questions raised over hospital negligence

| B Sridhar | TNN | Mar 14, 2026, 00:02 IST

Jamshedpur: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed report from West Singhbhum deputy commissioner and state health secretary into the March 7 incident where a man was forced to carry the body of his stillborn child away in a box for last rites after the staff of Chakradharpur subdivisional hospital allegedly denied him an ambulance.

A statement issued by the PIB on Friday said the NHRC has taken a suo motu cognisance of the incident and asked the DC and secretary to file the report within two weeks.

According to reports, Ramkrishna Hembram, of Bangarasai village, admitted his pregnant wife, Rita Tiriya, 28, to the hospital on March 5.

Hospital officials said that during check-up on Saturday, staff could not detect foetal heartbeat, and referred Rita for an ultrasound. Before the procedure could be completed, she began to experience labour pain and delivered a stillborn baby.

Hembram claimed that he sought an ambulance to transport the baby's body to his home, about 12 km away, but officials did not approve his request. As the ward boys allegedly insisted to promptly remove the body, he arranged a discarded cardboard box from the hospital premises. Hembram put the body in the box, packed it in a grocery bag and returned home in an e-rickshaw.



Source: <https://www.millenniumpost.in/nation/pending-mgnregs-dues-to-states-rs-9300-crore-in-fy26-govt-to-rs-651755>

NHRC steps in, seeks reports on missing children from 5 states

BY Naresh Biswani 14 Mar 2026 12:55 AM

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report which highlighted the fact that a huge number of cases of missing persons are pending in Bihar, a majority of whom are children. The media report states that between 12,000 and 14,000 cases of missing persons are registered every year in the state of Bihar since 2013. However, only two-thirds of the missing children have been found so far.

The NHRC has observed that “the matter is of serious concern to the Commission”. The contents of the media report, if true, reveal serious violations of human rights. The Commission is also concerned about the fact that even after taking various measures to deal with the issue of missing persons, the number of such cases is increasing while only a few cases are being successfully solved.”

According to the report, based on data provided by the National Crime Records Bureau (NCRB), it was observed that the highest numbers of human trafficking cases were registered in Odisha, Bihar, Telangana, and Maharashtra. Among these states, Odisha reported the highest numbers of cases related to the trafficking of minor boys, followed by Bihar. In the case of trafficking of minor girls, the highest numbers of incidents were reported in Rajasthan.

The media report, which was released on March 9, 2026, also raised concerns that some of these missing children could be engaged in illegal activities such as begging, child labour, prostitution, etc.

To address this issue, the NHRC has directed the Chief Secretaries of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, along with their respective Directors General of Police, to provide information on this issue within two weeks.



Source: <https://www.tribuneindia.com/news/haryana/nhrc-takes-cognisance-of-gurugram-wall-collapse-that-killed-7-workers/amp>

NHRC takes cognisance of Gurugram wall collapse that killed 7 workers

Seeks detailed report from government within two weeks

Tribune News Service

Gurugram, Updated At : 02:45 AM Mar 14, 2026 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of reports regarding the collapse of a wall at an under-construction site near Bilaspur in Gurugram that claimed the lives of at least seven workers and left three others injured on March 9.

According to reports, the incident occurred at a construction site where a sewage treatment plant (STP) was being built for an upcoming residential project. Several labourers were working at the site when a wall suddenly collapsed, trapping workers under the debris. Authorities initially feared that around 10 workers might have been trapped following the incident.

Taking serious note of the tragedy, the NHRC observed that if the reports were accurate, the incident raised serious concerns regarding the human rights of the victims, particularly in relation to workplace safety and the protection of labourers.

The Commission has issued notices to the Haryana Chief Secretary and the Gurugram Police Commissioner, directing them to submit a detailed report within two weeks.

The report has been sought on the current condition of the injured workers, progress in the investigation, and the compensation or relief provided to the families of the deceased as well as to the injured labourers.

According to media reports published on March 10, several rescue agencies were engaged in search and rescue operations after the collapse. Teams from the police, civil defence, fire department and the State Disaster Response Force (SDRF) jointly carried out operations to locate and rescue workers trapped under the rubble.

The incident has also raised concerns about construction site safety standards in Gurugram, a rapidly growing urban centre witnessing extensive residential and infrastructure development.



Source: <https://www.dailyexcelsior.com/nhrc-takes-cognisance-of-increasing-number-of-missing-people-poor-record-in-tracing-them/>

NHRC takes cognisance of 'increasing' number of missing people, 'poor' record in tracing them

By Daily Excelsior - March 14, 2026

NEW DELHI, Mar 13 : The NHRC on Friday said it has taken cognisance of a report that of the 12,000-14,000 missing persons' cases registered every year in Bihar since 2013, many of whom are children, "barely two-thirds of the missing children were recovered".

The data of the National Crime Records Bureau (NCRB) is believed to suggest that the maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra, it said.

Therefore, the rights panel has issued notices to the chief secretaries and director generals of police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, seeking a detailed report in two weeks, the rights panel said.

Odisha tops the list of the maximum number of minor boys trafficking cases followed by Bihar, the statement said.

In the trafficking of minor girls, Rajasthan apparently has registered the maximum cases.

According to a media report carried on March 9, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities, it said.

The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of human rights violations of the victims. It has also taken note of the reported concern that despite various measures taken by states, "the number of missing persons is increasing", and only "a few of them are traced", the statement said.

The report is expected to include the steps taken or proposed to be taken to deal with the increasing number of missing persons, especially children, the rights panel said.

Further, the Commission has sought the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these states within two weeks. (PTI)



Source: <https://tmv.in/article/jharkhand-tragedy-infant-dies-father-left-to-carry-babys-body-in-box-nhrc-steps-in-date=2026-03-14>

Jharkhand tragedy: Infant dies, father left to carry baby's body in box, NHRC steps in

Bavana Guntha

March 14, 2026

In a heartrending incident that has shaken public conscience, the father of a newborn in West Singhbhum, Jharkhand, was forced to carry his child's lifeless body in a cardboard box after the local hospital denied an ambulance.

The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognizance of the tragedy at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital, where lack of adequate care reportedly contributed to the infant's death. According to media reports, the hospital staff not only failed to provide necessary support during pre- and post-delivery care but also allegedly forced the family to remove the newborn's body from hospital premises.

The incident, which took place on 7th March 2026, highlights a serious violation of human rights, prompting the NHRC to issue notices to the Secretary, Department of Health, Medical Education & Family Welfare, Ranchi, and the Deputy Commissioner, West Singhbhum, seeking a detailed report within two weeks.

The Commission stated that if the reports are true, the lack of basic medical assistance and ambulance services reflects a grave negligence that warrants immediate investigation. The NHRC's move underscores the urgent need for accountability and improvements in maternal and infant healthcare in rural areas.

Local authorities are expected to submit a comprehensive explanation regarding the circumstances that led to this tragedy, including why the family was denied an ambulance and the steps the hospital took, or failed to take, to ensure the safety of the mother and child.

This case has ignited widespread concern across Jharkhand and beyond, with public calls for stricter monitoring of healthcare facilities and better emergency response systems. Human rights advocates insist that such lapses should never happen again, emphasizing the essential role of government oversight in protecting the most vulnerable.



Source: <https://www.greaterkashmir.com/national/nhrc-takes-cognisance-of-increasing-number-of-missing-people-poor-record-in-tracing-them/>

NHRC takes cognisance of 'increasing' number of missing people, 'poor' record in tracing them

The data of the National Crime Records Bureau (NCRB) is believed to suggest that the maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra, it said

PTI

March 13, 2026 11:55 pm

New Delhi, Mar 13: The NHRC on Friday said it has taken cognisance of a report that of the 12,000-14,000 missing persons' cases registered every year in Bihar since 2013, many of whom are children, "barely two-thirds of the missing children were recovered".

The data of the National Crime Records Bureau (NCRB) is believed to suggest that the maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra, it said.

Therefore, the rights panel has issued notices to the chief secretaries and director generals of police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, seeking a detailed report in two weeks, the rights panel said. Odisha tops the list of the maximum number of minor boys trafficking cases followed by Bihar, the statement said. In the trafficking of minor girls, Rajasthan apparently has registered the maximum cases.

According to a media report carried on March 9, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities, it said.

The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of human rights violations of the victims. It has also taken note of the reported concern that despite various measures taken by states, "the number of missing persons is increasing", and only "a few of them are traced", the statement said.

The report is expected to include the steps taken or proposed to be taken to deal with the increasing number of missing persons, especially children, the rights panel said.

Further, the Commission has sought the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these states within



Source: <https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc,-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-physical-assault-of-a-woman-from-manipur-by-a-group-of-boys-after-she-objeced-to-their-lewd-and-racial-abuse-in-malviya-nagar-area-of-south-delhi>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported physical assault of a woman from Manipur by a group of boys after she objected to their lewd and racial abuse in Malviya Nagar area of South Delhi

Press release

National Human Rights Commission

New Delhi: 13th March 2026

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported physical assault of a woman from Manipur by a group of boys after she objected to their lewd and racial abuse in Malviya Nagar area of South Delhi

Issues notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks

The report expected to include the status of health of victim and investigation

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a woman from Manipur was physically assaulted when she objected to lewd and racial abuse by a group of boys in the Malviya Nagar area of South Delhi. Reportedly, the incident happened on 8th March 2026.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks. It is expected to include the status of the victim's health and the investigation.

According to the media report, carried on 10th March 2026, the incident occurred when the victim was taking pictures with her friend at a park in the area.



Source: <https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc,-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-increasing-number-of-missing-people-and-the-poor-record-in-tracing-them>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported increasing number of missing people and the poor record in tracing them

Press release

National Human Rights Commission

New Delhi: 13th March 2026

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported increasing number of missing people and the poor record in tracing them

Reportedly, maximum cases of human trafficking registered in Odisha, Bihar, Telangana, Rajasthan and Maharashtra

Issues notices to Chief Secretaries and DGPs of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, calling for a detailed report on the matter within two weeks

The Commission also asks NCRB to provide the latest status of missing persons in these five states

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that of the 12,000 to 14,000 missing person cases registered every year in Bihar since 2013, many of which are children, barely two-thirds of the missing children were recovered. Reportedly, the data of National Crime Records Bureau (NCRB) suggests that maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra. Odisha tops the list of maximum number of minor boys trafficking cases followed by Bihar.

Reportedly, in trafficking of minor girls, Rajasthan has registered maximum cases. According to the media report, carried on 9th March 2026, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims. It has also taken note of the reported concerns that despite various measures taken by states, the number of missing persons is increasing and a few of them are traced. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the steps taken/ proposed to deal with the increasing number of missing persons, especially children. Further, the Commission has sought the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these states within two weeks.



Source: <https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc,-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-seven-workers-and-injuries-to-three-others-in-a-wall-collapse-at-an-under-construction-site-near-the-bilaspur-area-of-gurugram,-haryana>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of seven workers and injuries to three others in a wall collapse at an under-construction site near the Bilaspur area of Gurugram, Haryana

Press release

National Human Rights Commission

New Delhi: 13th March 2026

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of seven workers and injuries to three others in a wall collapse at an under-construction site near the Bilaspur area of Gurugram, Haryana

Issues notices to the state Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report on the matter within two weeks

The report expected to include the status of health of the injured persons, investigation, as well as compensation, if any, provided to the NoK of the deceased and the injured persons

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that at least seven workers died and three others were injured when a wall collapsed at an under-construction site near the Bilaspur area of Gurugram, Haryana on 9th March 2026. Reportedly, around ten more workers were feared trapped under the debris. The incident occurred at the site where a sewage treatment plant for an upcoming residential project is being constructed.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims. Therefore, it has issued notices to the state Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of health of the injured persons, investigation as well as compensation, if any, provided to the NoK of the deceased and the injured persons.

According to the media report, carried on 10th March 2026, the police as well as other agencies including the civil defence teams, rescue workers, fire fighters and personnel from the State Disaster Response Force were searching for the trapped workers under the debris.



Source: <https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc,-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-a-newborn-due-to-negligence-by-the-staff-of-chakradharpur-sub-divisional-hospital-in-west-singhbhum-district,-jharkhand>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of a newborn due to negligence by the staff of Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district, Jharkhand

Press release

National Human Rights Commission

New Delhi: 13th March 2026

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of a newborn due to negligence by the staff of Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district, Jharkhand

Reportedly, the father forced to carry the infant's body in a cardboard box to the village after denial of ambulance. Issues notices to Secretary, Department of Health, Medical Education & Family Welfare, Ranchi and Deputy Commissioner, West Singhbhum, Jharkhand, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that the lack of proper medical care for the mother and her baby during pre and post-delivery led to the death of her newborn at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district of Jharkhand. Reportedly, the father was forced to carry the infant's body in a cardboard box to Bangrasai village after being denied an ambulance by the hospital on 7th March 2026.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim. Therefore, it has issued notices to the Secretary, Department of Health, Medical Education & Family Welfare, Ranchi and Deputy Commissioner, West Singhbhum, Jharkhand, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 9th March 2026, the hospital staff forced the family to remove the body of the deceased baby from the hospital and refused to provide any assistance.



Source: <https://www.newsonair.gov.in/nhrc-issues-notice-to-delhi-police-commissioner-over-physical-assault-racial-abuse-of-woman/>

NHRC issues notice to Delhi Police Commissioner over physical assault & racial abuse of woman

News On AIR | March 13, 2026 4:33 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Delhi Police Commissioner over the reported physical assault and racial abuse of a woman from Manipur by a group of boys in the Malviya Nagar area of South Delhi. Taking suo motu cognisance of a media report, the NHRC has asked for a detailed report on the matter within two weeks. According to the media report carried on the 10th of this month, the incident occurred when the victim was taking pictures with her friend at a park in the area. The commission has observed that if the contents of the news report are true, it raises a serious issue of violation of the human rights of the victim.



Source: <https://pragativadi.com/nhrc-flags-odisha-in-child-trafficking-concerns/>

NHRC Seeks Report on Missing Persons; Odisha Tops in Minor Boys Trafficking Cases

by Yajati Rout | March 13, 2026 in Odisha

Reading Time: 1 min read

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of alarming reports highlighting a sharp rise in missing persons cases across India, with Odisha emerging as a major hotspot for human trafficking, particularly involving minor boys.

According to a media report cited by the NHRC, Odisha leads the country in registered cases of trafficking of minor boys, followed closely by Bihar. The National Crime Records Bureau (NCRB) data points to Odisha, Bihar, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan as the states recording the highest numbers of human trafficking incidents overall. In cases involving minor girls, Rajasthan tops the list.

The Commission expressed grave concern over the increasing number of missing persons—many of them children—and the reportedly poor success rate in tracing and recovering them. In Bihar alone, between 12,000 and 14,000 missing person cases have been registered annually since 2013, with many involving children; yet only about two-thirds are recovered. Similar patterns are feared in other high-risk states, including Odisha, where vulnerable children are suspected of being forced into begging, child labour, prostitution, and other exploitative illegal activities.

Describing these as serious human rights violations, the NHRC has issued formal notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police (DGPs) of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan. The authorities have been directed to submit a detailed report within two weeks, outlining:

- Steps already taken and those proposed to address the rising cases of missing persons, especially children.
- Measures to curb human trafficking networks.
- Progress on tracing and rehabilitating victims.

The Commission has also sought the latest statistical data directly from the NCRB on the status of missing persons in these five states within the same two-week period.



Source: <https://northeastlivetv.com/around-ne/manipur/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-assault-on-manipuri-woman-in-south-delhi-seeks-report-in-two-weeks/>

NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Assault on Manipuri Woman in South Delhi, Seeks Report in Two Weeks

Northeast Live Digital Desk March 13, 2026

First Published: 13th March, 2026 18:20 IST

Taking note of the report, the NHRC observed that if the allegations are found to be true, they raise a serious concern

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a reported incident in which a woman from Manipur was allegedly physically assaulted by a group of boys after she objected to lewd and racial remarks in South Delhi.

Acting on a media report, the Commission on Friday issued a notice to the Delhi Police Commissioner, Satish Golchha, seeking a detailed report on the incident within two weeks.

According to the report, the alleged assault took place on March 8 in the Malviya Nagar area of South Delhi when the woman was taking photographs with a friend at a park. A group of boys reportedly passed lewd and racially offensive comments at her. When she objected to the remarks, the situation escalated and she was allegedly physically assaulted.

Taking note of the report, the NHRC observed that if the allegations are found to be true, they raise a serious concern regarding the violation of the victim's human rights.

The Commission has asked the Delhi Police Commissioner to submit a comprehensive report detailing the action taken in the case. The report is also expected to include the current health condition of the victim as well as the status of the police investigation.

The NHRC stated that it initiated the proceedings on its own in view of the gravity of the allegations highlighted in the media report published on March 10.



Source: <https://nenews.in/manipur/nhrc-seeks-report-from-delhi-police-over-alleged-racial-assault-on-manipuri-woman/44699/>

NHRC seeks report from Delhi Police over alleged racial assault on Manipuri woman

By Northeast News

March 13, 2026 in Manipur

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed report from the Delhi Police Commissioner regarding the alleged assault of a woman from Manipur in South Delhi, reportedly linked to racial abuse.

The Commission issued a notice to Delhi Police Commissioner Satish Golchha, directing him to submit a report within two weeks.

The report is expected to include details on the progress of the investigation as well as the health condition of the victim.

According to officials, the NHRC took suo motu cognisance of a media report about the incident, which allegedly took place on March 8 in the Malviya Nagar area.

The woman was reportedly assaulted after she objected to lewd remarks and racial comments made by a group of youths.

The Commission noted that if the allegations reported in the media are found to be true, the incident would constitute a serious violation of the victim's human rights.

Reports indicate that the incident occurred while the woman and her friend were taking photographs at a park in the area.

In a separate matter, the NHRC has also issued notices to the Haryana Chief Secretary and the Gurugram Police Commissioner over the reported death of seven workers in a wall collapse in Bilaspur, Gurugram, on March 9.

The Commission has asked authorities to submit a detailed report on the incident within two weeks.



Source: [Nagaland Tribune https://nagalandtribune.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-reported-newborn-death-due-to-negligence-in-jharkhand/](https://nagalandtribune.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-reported-newborn-death-due-to-negligence-in-jharkhand/)

NHRC India takes suo motu cognizance of reported newborn death due to negligence in Jharkhand

NTN | March 13, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that the lack of proper medical care for the mother and her baby during pre and post-delivery led to the death of her newborn at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district of Jharkhand.

Reportedly, the father was forced to carry the infant's body in a cardboard box to Bangrasai village after being denied an ambulance by the hospital on March 7.

According to the Press Information Bureau (PIB), the Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim.

Therefore, it has issued notices to the Secretary, Department of Health, Medical Education & Family Welfare, Ranchi and Deputy Commissioner, West Singhbhum, Jharkhand, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report, carried on 9th March 2026, the hospital staff forced the family to remove the body of the deceased baby from the hospital and refused to provide any assistance.



Source: <https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/uttam-nagar-murder-nhrc-notice-to-police-chief-west-delhi-dm-for-action-taken-report-in-2-weeks-101773399264331.html>

Uttam Nagar murder: NHRC notice to police chief, West Delhi DM for action taken report in 2 weeks

Published on: Mar 13, 2026 4:24 PM IST

PTI

New Delhi, The NHRC has issued a notice to West Delhi's district magistrate and the city police commissioner in connection with the killing of a 26-year-old man in a clash in Uttam Nagar on Holi, and sought an action taken report from them within two weeks.

Uttam Nagar murder: NHRC notice to police chief, West Delhi DM for action taken report in 2 weeks

According to the proceedings of the case, the National Human Rights Commission has directed the authorities to conduct a "thorough and impartial investigation" into the March 4 incident.

The police have nabbed two juveniles and arrested 14 adults in connection with the killing of Tarun, who died during the clash between two groups of neighbours in Uttam Nagar's JJ Colony during a Holi celebration.

The NHRC, in its proceedings, dated March 10, said it has taken cognisance of the case after receiving a complaint. The complainant, Prakash, has alleged that Tarun was "brutally assaulted, lynched and killed by a group of Muslim individuals during the Holi celebrations in Uttam Nagar."

According to the complaint, the incident allegedly started after a minor accidental splash of water during the festivities, which led to a "dispute between the two families," reads the proceedings.

It is alleged that despite apologies from the victim's family, a group of around 15-20 persons attacked Tarun when he was returning home on a two-wheeler.

"The attackers reportedly used bricks, stones, and iron rods, causing severe injuries to the victim, who later died during treatment in the hospital," it says.

The complainant sought the intervention of the commission, and has requested to ensure a proper investigation, identification and prosecution of all persons involved, protection for the victim's family, and adequate compensation for the bereaved family, it adds.

The allegations made in the complaint, prima facie, seem to be "violations of the human rights of the victim."

A bench of the NHRC, presided by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance of the case under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

"The registry is directed to issue a notice to the district magistrate, West Delhi and Commissioner of Police, Delhi with directions to get the allegations made in the complaint inquired into," reads the proceedings.

The proceedings further reads it has been alleged through various media reports that the incident took place due to alleged "intolerance" during the Holi celebration.

"The investigating agency shall also examine and preserve all relevant evidence, including material and visual content circulating on social media platforms that may have evidentiary value, such as images or videos depicting potential forensic traces related to the incident," the NHRC says in its proceedings.

The authorities are directed to collect and secure CCTV footage from the vicinity of the place of occurrence, it adds.

"The investigating agency shall ensure that the crime scene has been properly secured and that all relevant forensic evidence, including fingerprints, footprints, stones or other objects allegedly used in the assault, and any other physical traces, are duly collected, preserved, and examined in accordance with established forensic procedures," the proceedings say.



Source: <https://english.mathrubhumi.com/amp/news/india/nhrc-acts-on-rising-missing-persons-cases-across-five-states-notices-issued-ut1usnya>

NHRC acts on rising missing persons cases across five states; notices issued

News Desk | Last Updated: 13 March 2026, 02:38 PM IST

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports highlighting the increasing number of missing persons and the poor rate of tracing them across several states in the country.

The Commission has issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, seeking a detailed report on the issue within two weeks.

According to reports, between 12,000 and 14,000 missing person cases have been registered every year in Bihar since 2013, many of them involving children. However, only about two-thirds of the missing children have been traced, raising concerns about their safety and possible exploitation.

The NHRC also took note of data from the National Crime Records Bureau (NCRB) suggesting that the highest number of human trafficking cases have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra. Odisha reportedly tops the list in cases involving the trafficking of minor boys, followed by Bihar, while Rajasthan records the highest number of cases involving the trafficking of minor girls.

Citing a media report published on March 9, the Commission noted concerns that many of the missing children are suspected to be forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

Observing that the contents of the report, if true, raise serious issues of human rights violations, the Commission said that despite measures taken by state authorities, the number of missing persons appears to be rising while only a limited number are traced.

The NHRC has therefore asked the concerned states to submit a detailed report within two weeks, outlining the steps taken or proposed to address the growing number of missing persons, particularly children.

Additionally, the Commission has sought the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these five states, also to be furnished within the same time frame. (ANI)



Source: <https://www.thehansindia.com/news/national/nhrc-takes-cognisance-of-assault-on-manipuri-woman-in-delhis-malviya-nagar-1056345>

NHRC takes cognisance of assault on Manipuri woman in Delhi's Malviya Nagar

Created On: 13 Mar 2026 6:47 PM IST

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report regarding the alleged physical assault of a woman from Manipur by a group of boys in South Delhi's Malviya Nagar area after she objected to lewd and racially abusive remarks.

Observing that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights, the apex human rights body has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

The NHRC said the report is expected to include the present status of the victim's health as well as the progress of the police investigation.

According to the media report, the incident occurred on March 8 when the victim was taking pictures with her transgender friend from Assam at a park in the Malviya Nagar locality.

Meanwhile, Delhi Police officials stated that four juveniles were apprehended during raids conducted in the locality after the incident was reported within the jurisdiction of the Malviya Nagar Police Station.

According to preliminary information, the victims — a woman from Manipur and a transgender person from Assam — were walking in a park near the Saket court complex when the group allegedly began making racially offensive remarks at them.

When the woman objected to the comments, the situation reportedly escalated into an argument, following which the group allegedly assaulted them -- punching them and hitting them with belts while also hurling abusive and derogatory slurs.

The injured woman was later taken to Safdarjung Hospital for medical examination and treatment. Authorities said she is currently stable and sustained minor injuries in the assault.

Earlier, Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma expressed anger over the incident, describing the assault as 'sickening,' and said that repeated attacks on people from the Northeast in mainland India are deeply concerning.



Source: <https://www.moneylife.in/article/nhrc-flags-human-trafficking-risk-in-missing-persons-cases-seeks-data-from-ncrb-and-5-states/79928.html>

NHRC Flags Human Trafficking Risk in Missing Persons Cases, Seeks Data from NCRB and 5 States

Moneylife Digital Team 13 March 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports highlighting the increasing number of missing persons and the low rate of tracing them in several states, raising serious concerns about possible human rights violations.

In a statement, the Commission says it had taken note of a report indicating that between 12,000 and 14,000 missing person cases have been registered every year in Bihar since 2013, many of them involving children. However, barely two-thirds of the missing children were reportedly traced, the Commission said.

Taking note of the gravity of the issue, NHRC has issued notices to the chief secretaries and directors general of police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan.

The Commission has asked the state authorities to submit a detailed report within two weeks outlining the steps taken or proposed to address the rising number of missing persons, particularly children.

NHRC also referred to data from the national crime records bureau (NCRB), which indicates that the highest number of human trafficking cases have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra.

Among these, Odisha reportedly records the highest number of cases involving trafficking of minor boys, followed by Bihar. In the trafficking of minor girls, Rajasthan has registered the maximum number of cases.

According to the media report cited by the Commission, many missing children are suspected to have been forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

NHRC says the contents of the report, if accurate, raise serious concerns regarding the violation of fundamental human rights of the victims.

The Commission also noted that despite various measures taken by state governments to address the issue, the number of missing persons continues to rise while only a portion of them are traced.

In addition to seeking reports from the five states, the Commission has also directed NCRB to provide the latest statistical data on the status of missing persons in these states.

The data will help the Commission assess the scale of the problem and evaluate the effectiveness of existing measures to trace missing persons.

NHRC says responses from state governments and the NCRB must be submitted within two weeks.



Source: <https://www.newsonair.gov.in/nhrc-issues-notices-to-haryana-chief-secretary-and-gurugram-police-commissioner-in-connection-with-workers-deaths-in-wall-collapse-case/>

NHRC issues notices to Haryana Chief Secretary and Gurugram Police Commissioner in connection with workers' deaths

News On AIR | March 13, 2026 1:23 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the state Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, in connection with a media report of the death of seven workers and injuries to three others in a wall collapse at an under-construction site near Bilaspur, Haryana. The media report cited that the police, as well as other agencies, including the civil defence teams, rescue workers, firefighters and personnel from the State Disaster Response Force, were searching for the trapped workers under the debris. Taking suo motu cognisance, NHRC has called for a detailed report on the matter within two weeks. It said that the contents of the report, if found true, raise serious issues of violation of the human rights of the victims.



Source: <https://thenewsmill.com/2026/03/nhrc-seeks-report-from-five-states-on-rise-in-missing-persons-cases/>

NHRC seeks report from five states on rise in missing persons cases

TNM (With ANI Inputs) | Published On: Mar 13, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports detailing an increase in missing persons and low recovery rates across several Indian states. Notices have been issued to the Chief Secretaries and Directors General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, requesting a detailed report within two weeks.

Reports indicate that Bihar has registered between 12,000 and 14,000 missing person cases annually since 2013, with many involving children. However, only about two-thirds of these missing children have been traced, raising concerns regarding their safety and the risk of exploitation.

The NHRC also noted data from the National Crime Records Bureau (NCRB) highlighting that Odisha, Bihar, Telangana, and Maharashtra report the highest numbers of human trafficking cases. According to the data, Odisha leads in trafficking cases involving minor boys, followed by Bihar. Rajasthan records the highest number of cases involving minor girls.

Citing a media report published on March 9, the Commission expressed concern that many missing children are suspected to have been forced into begging, child labour, prostitution, and other illegal activities.

The Commission stated that the reported issues raise serious human rights violations and observed that despite measures by state authorities, the number of missing persons continues to rise while only a limited number are recovered.

In response, the NHRC has directed the concerned states to provide a detailed account within two weeks of the steps taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children. The Commission has also requested the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these five states, to be submitted within the same timeframe.



Source: <https://www.livelaw.in/job-updates/inspector-vacancy-at-national-human-rights-commission-526262>

Inspector, National Human Rights Commission, Job

Manav Malhotra 13 March 2026

Inspector Vacancy At National Human...

Inspector Vacancy At National Human Rights Commission

Listen to this Article

National Human Rights Commission invites application for the post of Inspector on deputation basis.

Name of the Post: Inspector

No. of Post: 06 (Six)

Essential Qualification and Experience

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations; (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (b) with five years' service rendered after appointment to the post (as Sub-Inspector) on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and

Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute; and

With five years' experience in vigilance or investigation or intelligence work.

Desirable: Bachelor's degree with Law from a recognised University or recognised institute.

How to apply?

Interested candidates are required to submit in their application in the prescribed format and shall submit it to the office of Under Secretary (Estt.), National Human Rights Commission, Manav Adhikar Bhawan, 'C' Block, GPO Complex, INA, New Delhi — 110023 within 45 days from publication of advertisement in the newspapers.



Source: <https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-increasing-number-of-missing-people-and-the-poor-record-in-tracing-them/>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported increasing number of missing people and the poor record in tracing them

By iednewsdesk | March 13, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that of the 12,000 to 14,000 missing person cases registered every year in Bihar since 2013, many of which are children, barely two-thirds of the missing children were recovered. Reportedly, the data of National Crime Records Bureau (NCRB) suggests that maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra. Odisha tops the list of maximum number of minor boys trafficking cases followed by Bihar. Reportedly, in trafficking of minor girls, Rajasthan has registered maximum cases. According to the media report, carried on 9th March 2026, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims. It has also taken note of the reported concerns that despite various measures taken by states, the number of missing persons is increasing and a few of them are traced. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the steps taken/ proposed to deal with the increasing number of missing persons, especially children. Further, the Commission has sought the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these states within two weeks.



Source: <https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3836918-nhrc-demands-justice-26-year-old-killed-in-holi-clash>

NHRC Demands Justice: 26-Year-Old Killed in Holi Clash

The NHRC has instructed West Delhi's district magistrate and police commissioner to submit an action taken report regarding the Holi-day killing of a 26-year-old man in Uttam Nagar. The commission demands a thorough investigation into the incident, which allegedly resulted from a minor dispute during the celebrations.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 13-03-2026 16:22 IST | Created: 13-03-2026 16:22 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a directive to West Delhi's district magistrate and the city's police commissioner following the death of a 26-year-old man during Holi festivities in Uttam Nagar. The NHRC mandates a comprehensive and unbiased investigation, with an action taken report expected within two weeks.

In connection with the case, law enforcement has apprehended two juveniles and arrested 14 adults. The victim, identified as Tarun, allegedly suffered a brutal assault involving bricks and iron rods, leading to his death. The altercation reportedly began after a trivial incident involving water splashes during the celebrations.

Complaints allege accusations of human rights violations against Tarun, prompting the NHRC to intervene. The commission emphasizes evidence preservation, urging investigators to examine CCTV footage and any social media content of potential forensic value to ensure justice is served.

(With inputs from agencies.)



Source: <https://www.newsonair.gov.in/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-reported-death-of-newborn-in-west-singhbhum-jharkhand/>

NHRC takes suo motu cognizance of reported death of newborn in West Singhbhum, Jharkhand

News On AIR | March 13, 2026 1:14 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Secretary, Department of Health, Medical Education and Family Welfare, Ranchi and Deputy Commissioner, West Singhbhum, Jharkhand in connection with a media report of the death of a newborn due to lack of proper medical care. The media report has cited that the lack of proper medical care for the mother and her baby during pre and post-delivery led to the death of her newborn at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district of Jharkhand. Taking suo motu cognizance of the report, the NHRC has called for a detailed report on the matter within two weeks.



Source: <https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-physical-assault-of-a-woman-from-manipur-by-a-group-of-boys-after-she-objected-to-their-lewd-and-racial-abuse-in-malviya-nagar-area-of-south-delhi/>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported physical assault of a woman from Manipur by a group of boys after she objected to their lewd and racial abuse in Malviya Nagar area of South Delhi

By iednewsdesk

March 13, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a woman from Manipur was physically assaulted when she objected to lewd and racial abuse by a group of boys in the Malviya Nagar area of South Delhi. Reportedly, the incident happened on 8th March 2026.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks. It is expected to include the status of the victim's health and the investigation.

According to the media report, carried on 10th March 2026, the incident occurred when the victim was taking pictures with her friend at a park in the area.



Source: <https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-seven-workers-and-injuries-to-three-others-in-a-wall-collapse-at-an-under-construction-site-near-the-bilaspur-area-of-gurugram-haryana/>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of seven workers and injuries to three others in a wall collapse at an under-construction site near the Bilaspur area of Gurugram, Haryana

By iednewsdesk

March 13, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that at least seven workers died and three others were injured when a wall collapsed at an under-construction site near the Bilaspur area of Gurugram, Haryana on 9th March 2026. Reportedly, around ten more workers were feared trapped under the debris. The incident occurred at the site where a sewage treatment plant for an upcoming residential project is being constructed.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims. Therefore, it has issued notices to the state Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of health of the injured persons, investigation as well as compensation, if any, provided to the NoK of the deceased and the injured persons.

According to the media report, carried on 10th March 2026, the police as well as other agencies including the civil defence teams, rescue workers, fire fighters and personnel from the State Disaster Response Force were searching for the trapped workers under the debris.



Source: <https://jharkhandstatenews.com/article/top-stories/11065/explain-the-death-of-a-newborn-baby-due-to-lack-of-health-care-nhrc-asked-jharkhand-authorities>

Explain the death of a newborn baby due to lack of health care, NHRC asked Jharkhand authorities

Administrator

13 March 2026

The death of a newborn at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district of Jharkhand has become a major subject of inquiry by the National Human Rights Commission.

Already, NHRC has issued notices to the Secretary, Department of Health, Medical Education and Family Welfare, Ranchi and Deputy Commissioner, West Singhbhum, Jharkhand, in connection with a media report of the death of a newborn due to lack of proper medical care.

Investigation revealed that the lack of proper medical care for the mother and her baby during pre and post-delivery led to the death of her newborn at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district of Jharkhand.

After local newspapers reported the tragic event, the NHRC took suo motu cognizance of the report and has called for a detailed report on the matter within two weeks.



Source: <https://maktoobmedia.com/india/nhrc-seeks-report-after-father-carries-newborns-body-in-cardboard-box-from-jharkhand-hospital/>

NHRC seeks report after father carries newborn's body in cardboard box from Jharkhand hospital

Maktoob Staff | March 13, 2026

Modified : March 13, 2026

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of reports regarding the death of a newborn allegedly caused by negligence at a government hospital in Jharkhand's West Singhbhum district. According to a media report, inadequate medical care provided to the mother and her baby during pre- and post-delivery stages led to the death of the newborn at the Chakradharpur Sub-Divisional Hospital.

The incident reportedly occurred on March 7, when the infant died shortly after birth. The family alleged that hospital staff forced them to remove the baby's body from the premises and refused to provide further assistance.

In the absence of any support from the hospital authorities, the father was allegedly forced to carry the infant's body in a cardboard box to his native Bangrasai village after being denied an ambulance.

Taking note of the report published on March 9, the Commission observed that if the allegations are true, the incident raises a serious issue of violation of the human rights of the victim.

The rights body has issued notices to the Secretary of the Department of Health, Medical Education and Family Welfare in Ranchi and the Deputy Commissioner of West Singhbhum district, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

The Commission has asked the authorities to submit the factual status of the case and the action taken in response to the allegations.



Source: <https://www.thehawk.in/news/india/nhrc-seeks-report-from-delhi-cp-on-manipuri-womans-racial-abuse>

NHRC seeks report from Delhi CP on Manipuri woman's 'racial abuse'

The Hawk - Mar 13, 2026, 04:49 PM

New Delhi, March 13 (IANS) The NHRC has sought a report from Delhi Police Commissioner Satish Golchha within two weeks over an alleged incident of a Manipuri woman being physically assaulted as part of a "racial abuse", an official said on Friday.

The incident took place when she objected to lewd comments by a group of boys in the Malviya Nagar area of South Delhi in March, an official said on Friday.

The National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognisance of a media report that the woman from Manipur was physically assaulted when she objected to racial abuse. Reportedly, the incident happened on March 8, 2026.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights of the victim, said an official statement.

It issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks, adding that the report is expected to include the status of the victim's health and the investigation.

According to the media report, carried on March 10, 2026, the incident occurred when the victim was taking pictures with her friend at a park in the area, said the statement.

In a separate case, the NHRC has issued notices to Haryana Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report within two weeks on the alleged death of seven workers in a wall-collapse in the Bilaspur area of Gurugram on March 9.

Reportedly, around 10 more workers are feared trapped under the debris. The incident occurred at the site where a sewage treatment plant for an upcoming residential project was being constructed.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims.

Therefore, it issued notices to the state Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of health of the injured persons, investigation, as well as compensation, if any, provided to the next of kin of the deceased and the injured persons.

According to the media report, carried on March 10, the police, as well as other agencies, including the civil defence teams, rescue workers, fire fighters and personnel from the State Disaster Response Force, were searching for the trapped workers under the debris.

--IANS

rch/dan

Source: <https://www.thehawk.in/news/india/nhrc-seeks-report-from-delhi-authorities-over-alleged-lynching-of-dalit-youth-during-holi>

NHRC seeks report from Delhi authorities over alleged lynching of Dalit youth during Holi

NHRC Intervenes in Alleged Holi Violence Incident in Delhi

The Hawk • Mar 13, 2026, 03:44 PM

New Delhi, March 13 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the District Magistrate (West Delhi) and the Commissioner of Police, Delhi, over allegations that a 26-year-old Dalit youth was assaulted and lynched during Holi celebrations in th A Bench presided by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the incident occurred on March 4, after a minor dispute arising from an accidental splash of water during Holi festivities between two families.

According to the complaint, despite the victim's family offering apologies, a group of around 15-20 people allegedly attacked the youth later when he was returning home on a two-wheeler.

The attackers reportedly used bricks, stones, and iron rods, causing severe injuries. The victim later succumbed to his injuries during treatment at a hospital.

The complainant sought the NHRC's intervention and requested a proper investigation into the incident, identification and prosecution of all persons involved, protection for the victim's family, and adequate compensation for the bereaved family.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex rights body issued the notice under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The NHRC has directed the authorities to conduct a thorough and impartial investigation, ensure identification and prosecution of all accused persons, and assess the threat perception to the victim's family, taking appropriate measures for their safety as potential key witnesses.

It has also asked the investigating agency to examine and preserve all relevant evidence, including social media material, images, and videos that may have evidentiary value.

Authorities have been further directed to secure CCTV footage from the area, properly preserve the crime scene, and collect all relevant forensic evidence, such as fingerprints, footprints, stones, and other objects allegedly used in the assault.

The NHRC has sought an Action Taken Report (ATR) within two weeks for its perusal and directed authorities to forward a copy of the report via email.

--IANS

pds/dpb



Source: <https://www.lokmatimes.com/national/missing-persons-nhrc-seeks-reports-from-bihar-odisha-telangana-maha/amp/>

Missing persons: NHRC seeks reports from Bihar, Odisha, Telangana, Maha

By IANS | Updated: March 13, 2026 16:00 IST

New Delhi, March 13 Taking note of media reports on missing person cases, the NHRC has issued notices ...

New Delhi, March 13 Taking note of media reports on missing person cases, the NHRC has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, calling for a detailed report on the matter within two weeks, an official said on Friday.

The report is expected to include the steps taken/ proposed to deal with the increasing number of missing persons, especially children, said the official in a statement.

The National Human Rights Commission (NHRC) has also sought the latest statistical data from the National Crime Records Bureau (NCRB) on the status of missing persons in these states within two weeks.

The Commission has taken suo motu cognisance of a media report that of the 12,000 to 14,000 missing person cases registered every year in Bihar since 2013, many of which are children, barely two-thirds of the missing children were recovered.

Reportedly, the NCRB suggests that maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra.

Odisha tops the list of the maximum number of minor boys trafficking cases, followed by Bihar.

Reportedly, in the trafficking of minor girls, Rajasthan has registered the maximum cases. According to the media report, carried on March 9, 2026, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

The Commission has observed that the "contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims".

The NHRC has also taken note of the reported concerns that, despite various measures taken by states, the number of missing persons is increasing, and a few of them have been traced.

In a separate case, the Commission has taken suo motu cognisance of a media report that the lack of proper medical care for the mother and her baby during pre and post-delivery led to the death of her newborn at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district of Jharkhand.

The NHRC has issued notices to the Secretary, Department of Health, Medical Education and Family Welfare, Ranchi and Deputy Commissioner, West Singhbhum, Jharkhand, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

Reportedly, the father was forced to carry the infant's body in a cardboard box to Bangrasai village after being denied an ambulance by the hospital on March 7.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim.

--IANS

rch/dan



Source: <https://www.lokmatimes.com/national/nhrc-seeks-report-from-delhi-authorities-over-alleged-lynching-of-dalit-youth-during-holi/>

NHRC seeks report from Delhi authorities over alleged lynching of Dalit youth during Holi

By IANS | Updated: March 13, 2026 15:45 IST

New Delhi, March 13 The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the District Magistrate (West ...

New Delhi, March 13 The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the District Magistrate (West Delhi) and the Commissioner of Police, Delhi, over allegations that a 26-year-old Dalit youth was assaulted and lynched during Holi celebrations in the national Capital's Uttam Nagar.

A Bench presided by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the incident occurred on March 4, after a minor dispute arising from an accidental splash of water during Holi festivities between two families.

According to the complaint, despite the victim's family offering apologies, a group of around 15-20 people allegedly attacked the youth later when he was returning home on a two-wheeler.

The attackers reportedly used bricks, stones, and iron rods, causing severe injuries. The victim later succumbed to his injuries during treatment at a hospital.

The complainant sought the NHRC's intervention and requested a proper investigation into the incident, identification and prosecution of all persons involved, protection for the victim's family, and adequate compensation for the bereaved family.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex rights body issued the notice under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The NHRC has directed the authorities to conduct a thorough and impartial investigation, ensure identification and prosecution of all accused persons, and assess the threat perception to the victim's family, taking appropriate measures for their safety as potential key witnesses.

It has also asked the investigating agency to examine and preserve all relevant evidence, including social media material, images, and videos that may have evidentiary value.

Authorities have been further directed to secure CCTV footage from the area, properly preserve the crime scene, and collect all relevant forensic evidence, such as fingerprints, footprints, stones, and other objects allegedly used in the assault.

The NHRC has sought an Action Taken Report (ATR) within two weeks for its perusal and directed authorities to forward a copy of the report via email.



Source: <https://indiawhispers.com/2026/03/13/hindalco-hosts-national-human-rights-conference-in-bhubaneswar/>

Hindalco hosts National Human Rights Conference in Bhubaneswar

Posted by IW News Service | Mar 13, 2026 | Business

Bhubaneswar : Hindalco Industries Limited on Friday organized a National-level Human Rights Sensitization Conference in Bhubaneswar, bringing together policymakers, jurists, corporate leaders and civil society representatives from across the country for deliberations on rights-based development and ethical governance. The conference, held in collaboration with Human Rights Front, aimed to bring together diverse stakeholders to build a common and deeper understanding of human rights standards across industries.

By enabling cross-sector collaboration, the conference also sought to identify risks, bridge gaps and support the development of resilient, human rights-conscious organizations committed to responsible business conduct.

The inaugural session featured Dr. Justice Bidyut Ranjan Sarangi, Member of the National Human Rights Commission (NHRC); Justice Bimala Prasad Das, former Chairperson of the Odisha Human Rights Commission; Asim Amitabh Das, former Member of the OHRC; Dr. Nibedita Nath, Vice Chancellor of Maa Manikeswari University, Kalahandi; and Samik Basu, Chief Human Resources Officer of Hindalco Industries Limited. V.R. Shankar, Senior President and Chief Legal Officer, Hindalco; and T. M. Prakash, President–HR, Hindalco and Conference Convener were also present on the occasion.

Delivering the keynote address, Samik Basu emphasized the importance of embedding human rights values in corporate governance and development initiatives. “At Hindalco, respect for human rights is fundamental to how we operate. Anchored in our values of Integrity, Commitment and Seamlessness, we remain dedicated to building safe, inclusive and responsible workplaces. Safety and well-being lie at the core of our people philosophy, and this conference reinforces our belief that sustainable growth is only possible when dignity and care for every individual guide every decision,” said Basu emphasizing the company’s values-driven approach. Basu further highlighted that respect for human rights is integral to the company’s responsible business practices, strengthening trust, reducing risks and enhancing long-term resilience.

The company’s leadership in global ESG indices — including its top ranking as the World’s Most Sustainable Aluminium Company with an 87-point Corporate Sustainability Assessment (CSA) score — reflects its strong social, environmental and governance performance. A high ESG score of 89 in the S&P Global ESG assessment has further reinforced investor confidence and operational credibility while creating wider social impact through community development and ethical operations. Hindalco ranked as the world’s most sustainable aluminium company in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for six consecutive years, reinforcing the company’s ability to compete in global markets where sustainability increasingly determines access.

The conference featured three thematic panel discussions addressing key human rights issues. The first panel discussion focused on “Rights-Based Development: Advancing Equity, Inclusion and Institutional Accountability.” Moderated by senior journalist and former Bureau Chief of BBC Sandeep Sahu, the panel included Prof. (Dr.) Kumarbar Das, former Vice-Chancellor of FM University; V.R. Shankar, Senior President & Chief Legal Officer of Hindalco; Jagadananda, former State Information Commissioner; Dr. Kalpana Mallick, Member of the Odisha State Commission for Women; and Dr. Debasish Mahapatra, Associate Professor and Head of the Centre for Social Research & Innovation at KIIT University.

The second panel discussion examined “Corporate Responsibility and ESG,” focusing on ethical business practices and compliance with national and global human rights standards. The session was moderated by Nageswar Pattanaik, former Bureau Chief of The Economic Times, with panelists including Pratul Narayan, Associate Director

– ESG Advisory; Dr. Justice D. P. Choudhury, former Judge of the Orissa High Court; Dr. Rina Routray, Chairperson of Mahila Atmanirvar Abhiyan; and Dr. Ambika Prasad Nanda, Mentor at the Centre for Research & Community Action.

The final panel discussion addressed “Labour Codes and Human Rights: Balancing Ease of Doing Business with Worker Protection.” Moderated by Ganga C. Sharma, MD & CEO of Cetizion Verifica Pvt Ltd, the panel members were K. N. Gopinath, National Secretary of CITU; Daniel Umi, South Asia Head of Aide et Action; Girish Chandra Arya, All India Secretary of BMS; and Dr. Ashok Kumar Sahu, former Executive Director (H&A) of Nalco.

The conference also recognized several Human Rights Defenders for their contributions to promoting social justice. The valedictory session included Sitansu Mohan Dwibedy, Chairman of the Odisha State Bar Council; Ms. Namrata Chadha, former Member of the Odisha State Commission for Women; Basudeb Bhatta, President of Odisha Abhibhabak Mahasangha; Dr. Supriya Pattanayak, Vice Chancellor of Centurion University; and T. M. Prakash, President–HR, Hindalco.



Source: <https://menafn.com/1110856966/NHRC-Seeks-Report-From-Delhi-Authorities-Over-Alleged-Lynching-Of-Dalit-Youth-During-Holi>

NHRC Seeks Report From Delhi Authorities Over Alleged Lynching Of Dalit Youth During Holi

Date | 2026-03-13 06:15:28

(MENAFN- IANS) New Delhi, March 13 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the District Magistrate (West Delhi) and the Commissioner of Police, Delhi, over allegations that a 26-year-old Dalit youth was assaulted and lynched during Holi celebrations in the national Capital's Uttam Nagar.

A Bench presided by NHRC Member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint alleging that the incident occurred on March 4, after a minor dispute arising from an accidental splash of water during Holi festivities between two families.

According to the complaint, despite the victim's family offering apologies, a group of around 15-20 people allegedly attacked the youth later when he was returning home on a two-wheeler.

The attackers reportedly used bricks, stones, and iron rods, causing severe injuries. The victim later succumbed to his injuries during treatment at a hospital.

The complainant sought the NHRC's intervention and requested a proper investigation into the incident, identification and prosecution of all persons involved, protection for the victim's family, and adequate compensation for the bereaved family.

Observing that the allegations, if true, prima facie indicate violations of the human rights of the victim, the apex rights body issued the notice under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The NHRC has directed the authorities to conduct a thorough and impartial investigation, ensure identification and prosecution of all accused persons, and assess the threat perception to the victim's family, taking appropriate measures for their safety as potential key witnesses.

It has also asked the investigating agency to examine and preserve all relevant evidence, including social media material, images, and videos that may have evidentiary value.

Authorities have been further directed to secure CCTV footage from the area, properly preserve the crime scene, and collect all relevant forensic evidence, such as fingerprints, footprints, stones, and other objects allegedly used in the assault.

The NHRC has sought an Action Taken Report (ATR) within two weeks for its perusal and directed authorities to forward a copy of the report via email.



Source: <https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-rising-missing-persons-cases-seeks-report-from-five-states-7352407.html>

India News | NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Rising Missing Persons Cases, Seeks Report from Five States

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The Commission has issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, seeking a detailed report on the issue within two weeks.

Agency News ANI | Mar 13, 2026 01:20 PM IST

New Delhi [India], March 13 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of media reports highlighting the increasing number of missing persons and the poor rate of tracing them across several states in the country.

The Commission has issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, seeking a detailed report on the issue within two weeks.

According to reports, between 12,000 and 14,000 missing person cases have been registered every year in Bihar since 2013, many of them involving children. However, only about two-thirds of the missing children have been traced, raising concerns about their safety and possible exploitation.

The NHRC also took note of data from the National Crime Records Bureau (NCRB) suggesting that the highest number of human trafficking cases have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra. Odisha reportedly tops the list in cases involving the trafficking of minor boys, followed by Bihar, while Rajasthan records the highest number of cases involving the trafficking of minor girls.

Citing a media report published on March 9, the Commission noted concerns that many of the missing children are suspected to be forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

Observing that the contents of the report, if true, raise serious issues of human rights violations, the Commission said that despite measures taken by state authorities, the number of missing persons appears to be rising while only a limited number are traced.

The NHRC has therefore asked the concerned states to submit a detailed report within two weeks, outlining the steps taken or proposed to address the growing number of missing persons, particularly children.

Additionally, the Commission has sought the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these five states, also to be furnished within the same time frame. (ANI)

(The above story is verified and authored by ANI staff, ANI is South Asia's leading multimedia news agency with over 100 bureaus in India, South Asia and across the globe. ANI brings the latest news on Politics and Current Affairs in India & around the World, Sports, Health, Fitness, Entertainment, & News. The views appearing in the above post do not reflect the opinions of LatestLY)



Source: <https://theprint.in/india/uttam-nagar-murder-nhrc-notice-to-police-chief-west-delhi-dm-for-action-taken-report-in-2-weeks/2878080/?amp>

Uttam Nagar murder: NHRC notice to police chief, West Delhi DM for action taken report in 2 weeks

New Delhi, Mar 13 (PTI) The NHRC has issued a notice to West Delhi's district magistrate and the city police commissioner in connection with the killing of a 26-year-old man in a clash in Uttam Nagar on Holi, and sought an action taken report from them within two weeks. According to the proceedings of the [...]

PTI | 3 March, 2026 04:45 pm IST

New Delhi, Mar 13 (PTI) The NHRC has issued a notice to West Delhi's district magistrate and the city police commissioner in connection with the killing of a 26-year-old man in a clash in Uttam Nagar on Holi, and sought an action taken report from them within two weeks.

According to the proceedings of the case, the National Human Rights Commission has directed the authorities to conduct a "thorough and impartial investigation" into the March 4 incident.

The police have nabbed two juveniles and arrested 14 adults in connection with the killing of Tarun, who died during the clash between two groups of neighbours in Uttam Nagar's JJ Colony during a Holi celebration.

The NHRC, in its proceedings, dated March 10, said it has taken cognisance of the case after receiving a complaint. The complainant, Prakash, has alleged that Tarun was "brutally assaulted, lynched and killed by a group of Muslim individuals during the Holi celebrations in Uttam Nagar." According to the complaint, the incident allegedly started after a minor accidental splash of water during the festivities, which led to a "dispute between the two families," reads the proceedings.

It is alleged that despite apologies from the victim's family, a group of around 15–20 persons attacked Tarun when he was returning home on a two-wheeler.

"The attackers reportedly used bricks, stones, and iron rods, causing severe injuries to the victim, who later died during treatment in the hospital," it says.

The complainant sought the intervention of the commission, and has requested to ensure a proper investigation, identification and prosecution of all persons involved, protection for the victim's family, and adequate compensation for the bereaved family, it adds.

The allegations made in the complaint, prima facie, seem to be "violations of the human rights of the victim." A bench of the NHRC, presided by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance of the case under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

"The registry is directed to issue a notice to the district magistrate, West Delhi and Commissioner of Police, Delhi with directions to get the allegations made in the complaint inquired into," reads the proceedings.

The proceedings further reads it has been alleged through various media reports that the incident took place due to alleged "intolerance" during the Holi celebration.

"The investigating agency shall also examine and preserve all relevant evidence, including material and visual content circulating on social media platforms that may have evidentiary value, such as images or videos depicting potential forensic traces related to the incident," the NHRC says in its proceedings.

The authorities are directed to collect and secure CCTV footage from the vicinity of the place of occurrence, it adds.

"The investigating agency shall ensure that the crime scene has been properly secured and that all relevant forensic evidence, including fingerprints, footprints, stones or other objects allegedly used in the assault, and any other physical traces, are duly collected, preserved, and examined in accordance with established forensic

procedures," the proceedings say. PTI KND VN VN

This report is auto-generated from PTI news service. ThePrint holds no responsibility for its content.



Source: <https://indianews.com.au/missing-persons-nhrc-seeks-reports-from-bihar-odisha-telangana-maha/>

Missing persons: NHRC seeks reports from Bihar, Odisha, Telangana, Maha

BY India News Newsdesk

March 13, 2026

New Delhi, March 13 (IANS) Taking note of media reports on missing person cases, the NHRC has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, calling for a detailed report on the matter within two weeks, an official said on Friday.

The report is expected to include the steps taken/ proposed to deal with the increasing number of missing persons, especially children, said the official in a statement.

The National Human Rights Commission (NHRC) has also sought the latest statistical data from the National Crime Records Bureau (NCRB) on the status of missing persons in these states within two weeks.

The Commission has taken suo motu cognisance of a media report that of the 12,000 to 14,000 missing person cases registered every year in Bihar since 2013, many of which are children, barely two-thirds of the missing children were recovered.

Reportedly, the NCRB suggests that maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra.

Odisha tops the list of the maximum number of minor boys trafficking cases, followed by Bihar.

Reportedly, in the trafficking of minor girls, Rajasthan has registered the maximum cases. According to the media report, carried on March 9, 2026, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

The Commission has observed that the "contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims".

The NHRC has also taken note of the reported concerns that, despite various measures taken by states, the number of missing persons is increasing, and a few of them have been traced.

In a separate case, the Commission has taken suo motu cognisance of a media report that the lack of proper medical care for the mother and her baby during pre and post-delivery led to the death of her newborn at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district of Jharkhand.

The NHRC has issued notices to the Secretary, Department of Health, Medical Education and Family Welfare, Ranchi and Deputy Commissioner, West Singhbhum, Jharkhand, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

Reportedly, the father was forced to carry the infant's body in a cardboard box to Bangrasai village after being denied an ambulance by the hospital on March 7.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim.

-IANS

rch/dan



Source: <https://odishabytes.com/odisha-with-highest-cases-in-boys-trafficking-under-nhrc-lens-notices-issued-to-chief-secretary-dgp/>

Odisha, With Highest Cases In Boys' Trafficking, Under NHRC Lens; Notices Issued To Chief Secretary & DGP

by OB Bureau | March 13, 2026 in Odisha

Reading Time: 1 min read

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of media reports highlighting a sharp rise in missing persons cases across India, with Odisha leading the way in human trafficking of minor boys, according to National Crime Records Bureau (NCRB) data.

While Odisha tops minor boys' cases, outpacing Bihar, Rajasthan records the most minor girls trafficking instances.

Telangana and Maharashtra are the other states with high numbers in boys and girls trafficking.

Despite initiatives taken by states, recovery rates have been low, indicating deep human rights concerns and systemic gaps.

In Bihar, for instance, 12,000-14,000 cases are logged annually since 2013, many involving children, yet only about two-thirds of the missing minors are recovered, an NHRC release said.

As per a March 9 report, children are being coerced into begging, child labour, prostitution, and other crimes. Given the seriousness of the situation, NHRC has issued notices to Chief Secretaries and Directors General of Police in Odisha, Bihar, Telangana, Maharashtra and Rajasthan seeking detailed reports within two weeks on measures taken or planned to curb the surge, especially for children, alongside updated NCRB statistics on missing persons.



Source: <https://www.deccanchronicle.com/amp/nation/experts-at-human-rights-national-conference-call-for-rights-based-development-ethical-governance-1943601>

Experts At Human Rights National Conference Call For Rights-Based Development, Ethical Governance

The initiative encouraged knowledge sharing on best practices for integrating these principles into business operations while strengthening corporate responsibility frameworks aligned with national and international expectations: Reports

By : Akshaya Kumar Sahoo

Update: 2026-03-13 14:32 GMT

BHUBANESWAR: Reinforcing its commitment to responsible corporate citizenship and inclusive development, experts at the Human Rights National Conference on Friday called for rights-based development and ethical governance.

Held here, the one-day conference organised by Hindalco Industries Limited and Human Rights Front India brought together policymakers, jurists, corporate leaders and civil society representatives from across the country for deliberations on rights-based development and ethical governance.

The initiative encouraged knowledge sharing on best practices for integrating these principles into business operations while strengthening corporate responsibility frameworks aligned with national and international expectations. By enabling cross-sector collaboration, the conference also sought to identify risks, bridge gaps and support the development of resilient, human rights-conscious organizations committed to responsible business conduct.

The inaugural session featured Dr Justice Bidyut Ranjan Sarangi, Member of the National Human Rights Commission (NHRC); Justice Bimala Prasad Das, former Chairperson of the Odisha Human Rights Commission; Asim Amitabh Das, former Member of the OHRC; Dr. Nibedita Nath, Vice Chancellor of Maa Manikeswari University, Kalahandi; and Samik Basu, Chief Human Resources Officer of Hindalco Industries Limited. Shri V.R. Shankar, Senior President and Chief Legal Officer, Hindalco; HRFI chairperson Manoj Jena and T. M. Prakash, President-HR, Hindalco and Conference Convener were also present on the occasion.

Delivering the keynote address, Samik Basu emphasised the importance of embedding human rights values in corporate governance and development initiatives.

"At Hindalco, respect for human rights is fundamental to how we operate. Anchored in our values of Integrity, Commitment and Seamlessness, we remain dedicated to building safe, inclusive and responsible workplaces. Safety and well-being lie at the core of our people philosophy," he said.

The conference featured three thematic panel discussions addressing key human rights issues. The first panel discussion focused on Rights-Based Development: Advancing Equity, Inclusion and Institutional Accountability.' The second panel discussion examined 'Corporate Responsibility and ESG,' focusing on ethical business practices and compliance with national and global human rights standards. The final panel discussion addressed 'Labour Codes and Human Rights: Balancing Ease of Doing Business with Worker Protection.'

The conference also recognized several Human Rights Defenders for their contributions to promoting social justice.

The valedictory session included Sitansu Mohan Dwibedy, Chairman of the Odisha State Bar Council; Namrata Chadha, former Member of the Odisha State Commission for Women; Basudeb Bhatta, President of Odisha

Abhibhabak Mahasangha; Dr. Supriya Pattanayak, Vice Chancellor of Centurion University; and T. M. Prakash, President-HR, Hindalco.



Source: <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nhrc-takes-cognizance-of-reports-of-physical-assault-on-manipur-woman-in-delhi-malviya-nagar/articleshow/129559561.cms>

<https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nhrc-takes-cognizance-of-reports-of-physical-assault-on-manipur-woman-in-delhi-malviya-nagar/articleshow/129559561.cms>

NHRC takes cognizance of reports of physical assault on Manipur woman in Delhi's Malviya Nagar
Bikash Singh

Guwahati: The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognizance of the reported physical assault of a woman from Manipur by a group of boys after she objected to their lewd and racial abuse in the Malviya Nagar area of South Delhi.

A notice has been issued to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the victim's health and the investigation. The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognizance of a media report that a woman from Manipur was physically assaulted when she objected to lewd and racial abuse by a group of boys in the Malviya Nagar area of South Delhi. Reportedly, the incident happened on March 8, 2026.

The Commission has observed that the contents of the report, if true, raise a serious issue of violation of the victim's human rights. Therefore, it has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of the victim's health and the investigation.

According to the report, carried on March 10, 2026, the incident occurred when the victim was taking pictures with her friend at a park in the area.

The alleged assault of a woman from Manipur for objecting to harassment by a group of men near a park close to the Saket District Court complex in New Delhi on Sunday has evoked a sharp reaction in Northeast India.

The woman was taking a walk in the park when a group of men made inappropriate remarks towards them. When one of the women objected to the comments, the situation escalated and she was reportedly assaulted by the group.



Source: <https://indianews.com.au/nhrc-seeks-report-from-delhi-cp-on-manipuri-womans-racial-abuse/>

NHRC seeks report from Delhi CP on Manipuri woman's 'racial abuse'

BY India News Newsdesk

March 13, 2026

New Delhi, March 13 (IANS) The NHRC has sought a report from Delhi Police Commissioner Satish Golchha within two weeks over an alleged incident of a Manipuri woman being physically assaulted as part of a "racial abuse", an official said on Friday.

The incident took place when she objected to lewd comments by a group of boys in the Malviya Nagar area of South Delhi in March, an official said on Friday.

The National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognisance of a media report that the woman from Manipur was physically assaulted when she objected to racial abuse. Reportedly, the incident happened on March 8, 2026.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights of the victim, said an official statement.

It issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks, adding that the report is expected to include the status of the victim's health and the investigation.

According to the media report, carried on March 10, 2026, the incident occurred when the victim was taking pictures with her friend at a park in the area, said the statement.

In a separate case, the NHRC has issued notices to Haryana Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report within two weeks on the alleged death of seven workers in a wall-collapse in the Bilaspur area of Gurugram on March 9.

Reportedly, around 10 more workers are feared trapped under the debris. The incident occurred at the site where a sewage treatment plant for an upcoming residential project was being constructed.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims.

Therefore, it issued notices to the state Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of health of the injured persons, investigation, as well as compensation, if any, provided to the next of kin of the deceased and the injured persons.

According to the media report, carried on March 10, the police, as well as other agencies, including the civil defence teams, rescue workers, fire fighters and personnel from the State Disaster Response Force, were searching for the trapped workers under the debris.

-IANS

rch/dan



Source: <https://www.edexlive.com/news/nhrc-asks-report-on-alleged-racial-abuse-of-manipuri-woman-in-delhi>

NHRC asks report on alleged racial abuse of Manipuri woman in Delhi

NHRC took suo motu cognisance of a media report that the woman from Manipur was physically assaulted when she objected to racial abuse

NHRC asks report on alleged racial abuse of Manipuri woman in Delhi

IANS

Updated on: 13 Mar 2026, 8:20 pm

New Delhi, March 13 (IANS): The NHRC has sought a report from Delhi Police Commissioner Satish Golchha within two weeks over an alleged incident of a Manipuri woman being physically assaulted as part of a "racial abuse", an official said on Friday.

The incident took place when she objected to lewd comments by a group of boys in the Malviya Nagar area of South Delhi in March, an official said on Friday.

The National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognisance of a media report that the woman from Manipur was physically assaulted when she objected to racial abuse. Reportedly, the incident happened on March 8, 2026.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights of the victim, said an official statement.

It issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks, adding that the report is expected to include the status of the victim's health and the investigation.

According to the media report, carried on March 10, 2026, the incident occurred when the victim was taking pictures with her friend at a park in the area, said the statement.

In a separate case, the NHRC has issued notices to Haryana Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report within two weeks on the alleged death of seven workers in a wall-collapse in the Bilaspur area of Gurugram on March 9.

Reportedly, around 10 more workers are feared trapped under the debris. The incident occurred at the site where a sewage treatment plant for an upcoming residential project was being constructed.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims.

Therefore, it issued notices to the state Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of health of the injured persons, investigation, as well as compensation, if any, provided to the next of kin of the deceased and the injured persons.

According to the media report, carried on March 10, the police, as well as other agencies, including the civil defence teams, rescue workers, fire fighters and personnel from the State Disaster Response Force, were searching for the trapped workers under the debris.

(IANS)



Source: <https://ommcomnews.com/india-news/missing-persons-nhrc-seeks-reports-from-bihar-odisha-telangana-maha/>

Missing Persons: NHRC Seeks Reports From Bihar, Odisha, Telangana, Maha

by OMMCOM NEWS

March 13, 2026 in Nation

New Delhi: Taking note of media reports on missing person cases, the NHRC has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, calling for a detailed report on the matter within two weeks, an official said on Friday.

The report is expected to include the steps taken/ proposed to deal with the increasing number of missing persons, especially children, said the official in a statement.

The National Human Rights Commission (NHRC) has also sought the latest statistical data from the National Crime Records Bureau (NCRB) on the status of missing persons in these states within two weeks.

The Commission has taken suo motu cognisance of a media report that of the 12,000 to 14,000 missing person cases registered every year in Bihar since 2013, many of which are children, barely two-thirds of the missing children were recovered.

Reportedly, the NCRB suggests that maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra.

Odisha tops the list of the maximum number of minor boys trafficking cases, followed by Bihar.

Reportedly, in the trafficking of minor girls, Rajasthan has registered the maximum cases. According to the media report, carried on March 9, 2026, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

The Commission has observed that the "contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims".

The NHRC has also taken note of the reported concerns that, despite various measures taken by states, the number of missing persons is increasing, and a few of them have been traced.

In a separate case, the Commission has taken suo motu cognisance of a media report that the lack of proper medical care for the mother and her baby during pre and post-delivery led to the death of her newborn at Chakradharpur Sub-Divisional Hospital in West Singhbhum district of Jharkhand.

The NHRC has issued notices to the Secretary, Department of Health, Medical Education and Family Welfare, Ranchi and Deputy Commissioner, West Singhbhum, Jharkhand, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

Reportedly, the father was forced to carry the infant's body in a cardboard box to Bangrasai village after being denied an ambulance by the hospital on March 7.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim.

(IANS)



Source: <https://nagalandtribune.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-reported-death-of-seven-workers-in-gurugram/>

NHRC India takes suo motu cognizance of reported death of seven workers in Gurugram

NTN | March 13, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that at least seven workers died and three others were injured when a wall collapsed at an under-construction site near the Bilaspur area of Gurugram, Haryana on March 9. Reportedly, around ten more workers were feared trapped under the debris. The incident occurred at the site where a sewage treatment plant for an upcoming residential project is being constructed.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims. Therefore, it has issued notices to the state Chief Secretary and the Police Commissioner, Gurugram, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of health of the injured persons, investigation as well as compensation, if any, provided to the NoK of the deceased and the injured persons.

According to the media report, carried on March 10, the police as well as other agencies including the civil defence teams, rescue workers, fire fighters and personnel from the State Disaster Response Force were searching for the trapped workers under the debris.



Source: <https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-physical-assault-of-a-woman-from-manipur-by-a-group-of-boys-after-she-objeced-to-their-lewd-and-racial-abuse-in-malviya-nagar-area-of-south-delhi/>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported physical assault of a woman from Manipur by a group of boys after she objected to their lewd and racial abuse in Malviya Nagar area of South Delhi

By:Odisha Diary Bureau

Date: March 13, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a woman from Manipur was physically assaulted when she objected to lewd and racial abuse by a group of boys in the Malviya Nagar area of South Delhi. Reportedly, the incident happened on 8th March 2026.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights of the victim. Therefore, it has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, calling for a detailed report on the matter within two weeks. It is expected to include the status of the victim's health and the investigation.

According to the media report, carried on 10th March 2026, the incident occurred when the victim was taking pictures with her friend at a park in the area.



Source: <https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-increasing-number-of-missing-people-and-the-poor-record-in-tracing-them/>

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported increasing number of missing people and the poor record in tracing them

By:Odisha Diary Bureau

Date: March 13, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that of the 12,000 to 14,000 missing person cases registered every year in Bihar since 2013, many of which are children, barely two-thirds of the missing children were recovered. Reportedly, the data of National Crime Records Bureau (NCRB) suggests that maximum cases of human trafficking have been registered in Odisha, Bihar, Telangana and Maharashtra. Odisha tops the list of maximum number of minor boys trafficking cases followed by Bihar.

Reportedly, in trafficking of minor girls, Rajasthan has registered maximum cases. According to the media report, carried on 9th March 2026, it is suspected that these children are forced into begging, child labour, prostitution and other illegal activities.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations of the victims. It has also taken note of the reported concerns that despite various measures taken by states, the number of missing persons is increasing and a few of them are traced. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra and Rajasthan, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the steps taken/ proposed to deal with the increasing number of missing persons, especially children. Further, the Commission has sought the latest statistical data from the NCRB on the status of missing persons in these states within two weeks.



Source: <https://www.lokmatimes.com/national/nhrc-takes-cognisance-of-assault-on-manipuri-woman-in-delhis-malviya-nagar/amp/>

NHRC takes cognisance of assault on Manipuri woman in Delhi's Malviya Nagar

By IANS | Updated: March 13, 2026 18:35 IST

New Delhi, March 13 The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media ...

NHRC takes cognisance of assault on Manipuri woman in Delhi's Malviya Nagar

New Delhi, March 13 The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report regarding the alleged physical assault of a woman from Manipur by a group of boys in South Delhi's Malviya Nagar area after she objected to lewd and racially abusive remarks.

Observing that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights, the apex human rights body has issued a notice to the Delhi Police Commissioner, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

The NHRC said the report is expected to include the present status of the victim's health as well as the progress of the police investigation.

According to the media report, the incident occurred on March 8 when the victim was taking pictures with her transgender friend from Assam at a park in the Malviya Nagar locality.

Meanwhile, Delhi Police officials stated that four juveniles were apprehended during raids conducted in the locality after the incident was reported within the jurisdiction of the Malviya Nagar Police Station.

According to preliminary information, the victims — a woman from Manipur and a transgender person from Assam — were walking in a park near the Saket court complex when the group allegedly began making racially offensive remarks at them.

When the woman objected to the comments, the situation reportedly escalated into an argument, following which the group allegedly assaulted them -- punching them and hitting them with belts while also hurling abusive and derogatory slurs.

The injured woman was later taken to Safdarjung Hospital for medical examination and treatment. Authorities said she is currently stable and sustained minor injuries in the assault.

Earlier, Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma expressed anger over the incident, describing the assault as 'sickening,' and said that repeated attacks on people from the Northeast in mainland India are deeply concerning.

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor



Source: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/haryana-rights-panel-seeks-aid-policy-for-deaths-in-police-custody/articleshow/129521903.cms>

Haryana rights panel seeks aid policy for deaths in police custody

Mar 13, 2026, 06.14 AM IST

Gurgaon: The Haryana Human Rights Commission directed the state govt and the state police to frame a compensation policy for deaths, torture and other violations in police custody on the lines of the existing policy for deaths in judicial custody. Commission member Deep Bhatia said the framework must mirror the existing compensation mechanism to ensure uniform accountability and compensation across all custody-related cases. In 2021, the state implemented India's first compensation policy for unnatural deaths in judicial custody—offering Rs 7.5 lakh in cases involving assault, torture or negligence by prison officials, and Rs 5 lakh for deaths caused by medical negligence. The policy was subsequently endorsed by the National Human Rights Commission. Bhatia was hearing a case of alleged custodial violations where the complainant argued that families of victims of police custody violence face uncertainty due to the absence of a structured compensation regime. The commission observed that the state cannot maintain two separate standards—one for judicial custody and another for police custody. The Commission directed the govt to finalize a policy, in consultation with relevant departments, ensuring timely compensation as a constitutional mandate. The policy must clearly outline violation categories, assessment procedures, compensation amounts, and disbursement timelines.



Source: <https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-issues-notice-to-five-states-over-rise-in-missing-persons-cases/article70740085.ece>

NHRC issues notices to five States over rise in missing persons cases

The Commission takes cognisance of media reports indicating 12,000 and 14,000 missing persons cases annually since 2013 in Bihar alone; observes the issue raises serious concerns of human rights violations

Published - March 13, 2026 09:20 pm IST - New Delhi

The Hindu Bureau

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday (March 13, 2026) issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police (DGPs) of Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, and Rajasthan, expressing concern over the growing number of missing persons reported in these States.

The Commission took cognisance of media reports indicating that Bihar has recorded between 12,000 and 14,000 missing persons cases annually since 2013, a significant proportion of them involving children. Reports suggest that only around two-thirds of the missing children have been traced.

Govt. gets NHRC notice seeking report on missing person cases

Children most affected

Referring to data from the National Crime Records Bureau (NCRB), the NHRC noted that the highest number of human trafficking cases has been reported in Odisha, Bihar, Telangana, and Maharashtra.

Odisha recorded the largest number of cases involving trafficking of minor boys, followed by Bihar, while Rajasthan reported most cases involving trafficking of minor girls.

NHRC issues notice to Madhya Pradesh government over police inaction in finding a missing girl

According to the reports, some missing children are suspected to be forced into begging, child labour, prostitution and other unlawful activities.

Observing that the issue raises serious concerns of human rights violations, the Commission has asked the authorities in the five States to submit a detailed report within two weeks.

The NHRC also took note of concerns that the number of missing persons continues to rise despite measures taken by the States, and that only a limited number of cases are successfully traced.

The Commission has sought information on steps already taken or proposed to address the increasing number of missing persons, particularly children. It has also requested the NCRB to provide the latest statistical data on the status of missing persons in these States within the same timeframe.



Source: <https://www.tribuneindia.com/news/haryana/nhrc-takes-notice-of-gurugram-wall-collapse-that-killed-7-workers-seeks-report/amp>

NHRC takes notice of Gurugram wall collapse that killed 7 workers, seeks report

According to media reports, the incident occurred at a construction site where a sewage treatment plant (STP) was being built for an upcoming residential project

Sumedha Sharma

Tribune News Service

Gurugram, Updated At : 07:31 PM Mar 13, 2026 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of reports of a tragic wall collapse at an under-construction site near the Bilaspur area of Gurugram, Haryana, which claimed the lives of at least seven workers and left three others injured on March 9, 2026.

According to media reports, the incident occurred at a construction site where a sewage treatment plant (STP) was being built for an upcoming residential project. Several labourers were working at the site when the wall suddenly collapsed, trapping multiple workers under the debris. Authorities feared that around 10 workers could have been trapped immediately after the incident.

Taking serious note of the matter, NHRC observed that if the reports are accurate, the incident raises significant concerns regarding human rights violations of the victims, particularly relating to workplace safety and protection of labourers. The commission has issued notices to the Haryana Chief Secretary and the Gurugram Police Commissioner, directing them to submit a detailed report within two weeks.

The report must include the current health status of the injured workers, details of the ongoing investigation, and information regarding compensation or relief provided to the next of kin of the deceased and the injured labourers.

A media report published on March 10 stated that multiple rescue agencies were involved in search and rescue operations following the collapse. Teams from the police, civil defence, and fire departments, and State Disaster Response Force (SDRF) worked together to locate and rescue workers trapped under the rubble.

The incident has raised serious concerns about construction site safety standards in Gurugram, a rapidly expanding urban hub with numerous ongoing residential and infrastructure projects. Authorities are now expected to examine whether safety protocols and labour protection norms were followed at the site.



Source:

<https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2026/Mar/13/karnataka-hc-orders-probe-into-encounter-of-rape-murder-accused>

Karnataka HC orders probe into encounter of rape-murder accused

The court was hearing the public interest litigation, filed in 2025 by People's Union for Civil Liberties-Karnataka, and Dr Madhu Bhushan.

Express News Service

Updated on: 13 Mar 2026, 8:56 am

2 min read

BENGALURU: The Karnataka High Court ordered a judicial magistrate enquiry into the alleged 2025 police encounter of a migrant labourer, who was accused of rape and murder of a minor girl in Hubballi-Dharwad. The HC said the enquiry report should be submitted on June 8, 2026. Referring to the directions issued by the Supreme Court in People's Union for Civil Liberties, the division bench of Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice CM Poonacha directed that those norms must be strictly observed in all cases of death and grievous injury in police encounters by treating them as law declared under Article 141 of the Constitution of India.

The judicial magistrate concerned should also bear in mind the guidelines issued by the National Human Rights Commission for conducting an inquiry in cases of death in custody or in the course of police action, said the HC, in the order passed recently.

The court was hearing the public interest litigation, filed in 2025 by People's Union for Civil Liberties-Karnataka, and Dr Madhu Bhushan. The counsel said instead of filing an FIR for custodial death, it was filed against the accused-deceased, and no police officials were named.

There should be a magisterial enquiry in accordance with Section 196 of the BNSS. An enquiry by an Executive Magistrate was conducted, which is not in conformity with the directions issued by the apex court, the counsel argued.

Advocate General K Shashikiran Shetty said that there is no requirement to name the police officials as accused, as the entire incident is recorded, and that if any further offences are to be added, the same can be done at an appropriate stage. He assured that all aspects of the incident recorded would be investigated by the CID, including the role of the police officials.

Insofar as the conduct of enquiry by a judicial magistrate is concerned, he submitted that there is no objection for this court to issue directions in this regard. In fact, a reference was made for conducting an enquiry by a judicial Magistrate. However, the same was declined on a misreading of the directions issued by the apex court, he argued.

On April 13, 2025, at around 10.45 am, the police received information regarding a body of a child, which was abandoned near a shed in Vijayanagar. The accused took the police to the outskirts of an abandoned house, where he resided, where the child's body was found.

The accused was shot near that house. As the accused tried to escape by pelting stones at the police, and tried to strangulate a woman constable. Two warning shots were fired. Thereafter, three shots were fired at him, and he succumbed to the same.

Source: <https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-nhrc-raises-alarm-on-rising-missing-persons-in-india-seeks-reports-from-five-states-201773422933991.html>

लापता लोगों के बढ़ते मामलों पर एनएचआरसी सख्त, पांच राज्यों से रिपोर्ट मांगी

Mar 13, 2026 10:58 pm IST हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

-नाबालिग लड़कों की तस्करी के मामलों में ओडिशा पहले स्थान -नाबालिग लड़कियों की तस्करी के नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में लापता लोगों की बढ़ती संख्या और खराब रिकॉर्ड पर संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में पांच राज्यों से दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 से बिहार में हर साल करीब 12,000 से 14,000 लोग लापता होने के मामले दर्ज होते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। इनमें से करीब दो-तिहाई बच्चों को ही बरामद किया जा सका है। एनएचआरसी ने इस मामले में बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किया है और उनसे विस्तृत जानकारी मांगी है। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। वहीं नाबालिग लड़कों की तस्करी के मामलों में ओडिशा पहले स्थान पर है, जिसके बाद बिहार का स्थान है। जबकि नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामलों में राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खतरा है कि लापता बच्चों को भीख मांगना, बाल मजदूरी, देह व्यापार और अन्य अवैध गतिविधियों में धकेला जा रहा है। एनएचआरसी ने कहा कि यदि ये खबरें सही हैं तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने यह भी चिंता जताई कि राज्यों द्वारा कई कदम उठाने के बावजूद लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत कम लोगों को ही ढूंढा जा पा रहा है।



Source: <https://azadsipahi.in/03/2026/nhrc-took-cognizance-of-death-of-newborn-in-west-singhbhum-issued-notice.html>

एनएचआरसी ने लिया पश्चिम सिंहभूम में नवजात की मौत का संज्ञान, जारी किया नोटिस

By shivam kumar March 13, 2026 1 Min Read

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की कथित मृत्यु का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने रांची स्थित स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बताया कि 9 मार्च 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस न दिए जाने के बाद पिता को शिशु के शव को गते के बक्से में रखकर बंगरासाई गांव ले जाना पड़ा। खबरों के मुताबिक, अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार को मृत शिशु के शव को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए मजबूर किया और किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया था।

Source: https://www.jagran.com/odisha/bhubaneswar-nhrc-demands-report-on-missing-persons-from-5-states-40170199.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

लापता लोगों के बढ़ते मामलों पर NHRC सख्त, ओडिशा-बिहार समेत 5 राज्यों से मांगी रिपोर्ट

By Sheshnath Rai Edited By: Rajat Mourya

Updated: Fri, 13 Mar 2026 03:15 PM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में लापता लोगों की बढ़ती संख्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे गंभीर मानवाधिकार मुद्दा मानते हुए ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकारों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। लापता लोगों के बढ़ते मामलों पर NHRC सख्त, ओडिशा-बिहार समेत 5 राज्यों से मांगी रिपोर्ट

HighLights

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लापता लोगों पर स्वतः संज्ञान लिया।

ओडिशा, बिहार सहित पांच राज्यों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट।

लापता बच्चों के शोषण और तस्करी पर गंभीर चिंता जताई।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में लापता लोगों की बढ़ती संख्या और उन्हें तलाशने के खराब रिकॉर्ड पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीर मानवाधिकार मुद्दा मानते हुए ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने इन पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से भी इन राज्यों में लापता लोगों की ताजा स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013 से बिहार में हर साल करीब 12 से 14 हजार लोगों के लापता होने के मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। इनमें से मुश्किल से दो-तिहाई बच्चों को ही बरामद किया जा सका है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। नाबालिग लड़कों की तस्करी के मामलों में ओडिशा सबसे ऊपर है, जबकि नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर है।

रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि लापता बच्चों को भीख मंगवाने, बाल मजदूरी, देह व्यापार और अन्य अवैध गतिविधियों में जबरन लगाया जा रहा है।

आयोग ने कहा कि यदि रिपोर्ट में दी गई बातें सही हैं तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने यह भी चिंता जताई कि राज्यों द्वारा विभिन्न कदम उठाने के बावजूद लापता लोगों की संख्या बढ़ रही है और बहुत कम मामलों में ही उनका पता चल पा रहा है।

एनएचआरसी ने राज्यों से यह भी बताने को कहा है कि लापता लोगों, खासकर बच्चों के मामलों को रोकने और उन्हें जल्द खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या आगे क्या योजना है।

Source: <https://www.livehindustan.com/ncr/uttam-nagar-murder-nhrc-notice-to-police-chief-west-delhi-dm-for-action-taken-report-201773402153118.amp.html>

दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड में NHRC का ऐक्शन, पुलिस कमिश्नर और DM को नोटिस; क्या निर्देश

Mar 13, 2026 05:25 pm IST

Subodh Kumar Mishra | पीटीआई, नई दिल्ली

होली के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर में हुई युवक की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐक्शन लिया है। आयोग ने पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

होली के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर में हुई युवक की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐक्शन लिया है। आयोग ने पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को घटना की पूरी और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश भी दिया है।

उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दौरान पड़ोसियों के दो गुटों के बीच हुई झड़प में तरुण की मौत के सिलसिले में पुलिस ने दो नाबालिगों को पकड़ा है और 14 वयस्कों को गिरफ्तार किया है। एनएचआरसी ने 10 मार्च को अपनी कार्यवाही में कहा कि शिकायत मिलने के बाद उसने इस मामले का संज्ञान लिया है।

पानी की छींटे पड़ने से शुरू हुआ झगड़ा

शिकायतकर्ता प्रकाश ने आरोप लगाया है कि उत्तम नगर में होली के उत्सव के दौरान मुस्लिम व्यक्तियों के एक समूह ने तरुण पर बेरहमी से हमला किया और उसे पीट-पीटकर मार डाला। शिकायत के अनुसार, यह घटना उत्सव के दौरान पानी के मामूली छींटे पड़ने से शुरू हुई, जिसके कारण दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ।

ईट, पत्थरों और लोहे की छड़ों का इस्तेमाल

आरोप है कि पीड़ित परिवार द्वारा माफी मांगने के बावजूद लगभग 15-20 लोगों के एक समूह ने तरुण पर तब हमला किया जब वह दोपहिया वाहन से घर लौट रहा था। शिकायत में कहा गया है कि हमलावरों ने ईटों, पत्थरों और लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया। इस हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पर्याप्त मुआवजे की भी मांग

शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है और उचित जांच सुनिश्चित करने, सभी आरोपियों की पहचान और उन पर मुकदमा चलाने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और पर्याप्त मुआवजा देने का अनुरोध किया है। शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

एनएचआरसी की पीठ ने संज्ञान लिया

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक पीठ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रियांक कानूनगो ने कार्यवाही में लिखा है कि रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करे और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने का निर्देश दे।

सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश

कार्यवाही में आगे लिखा है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह आरोप लगाया गया है कि होली के दौरान कथित असहिष्णुता के कारण यह घटना घटी। कार्यवाही में कहा गया है कि जांच एजेंसी सभी प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच करेगी और उन्हें सुरक्षित रखेगी। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित सामग्री भी शामिल है, जिनका साक्ष्य के रूप में महत्व हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि अधिकारियों को घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को एकत्र करने और सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है।

कार्यवाही में कहा गया है कि जांच एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अपराध स्थल पर उंगलियों के निशान, पैरों के निशान, पत्थर या हमले में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई अन्य वस्तुएं, अन्य भौतिक निशान सहित सभी फॉरेंसिक साक्ष्य विधिवत एकत्र, संरक्षित और जांच किए गए हैं।

Source: <https://hindi.theprint.in/india/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-rising-missing-persons-cases-seeks-report-from-5-states-within-two-weeks/944859/>

लापता लोगों के बढ़ते मामलों पर NHRC का स्वतः संज्ञान, 5 राज्यों से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

आयोग ने 9 मार्च को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई लापता बच्चों के बारे में आशंका है कि उन्हें भीख मंगवाने, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में जबरन लगाया जा सकता है.

एनएआई

13 March, 2026

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के कई राज्यों में लापता लोगों के बढ़ते मामलों और उन्हें ढूंढने की कम दर को लेकर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है.

आयोग ने बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर दो हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

रिपोर्टों के अनुसार, बिहार में 2013 से हर साल लगभग 12,000 से 14,000 तक लापता व्यक्तियों के मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनमें से कई मामले बच्चों से जुड़े हैं. हालांकि, लापता बच्चों में से केवल लगभग दो-तिहाई को ही खोजा जा सका है, जिससे उनकी सुरक्षा और संभावित शोषण को लेकर चिंता बढ़ गई है. एनएचआरसी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का भी संज्ञान लिया है. इन आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं. नाबालिग लड़कों की तस्करी के मामलों में ओडिशा सबसे ऊपर है, उसके बाद बिहार का स्थान है, जबकि नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामलों में राजस्थान सबसे आगे है.

आयोग ने 9 मार्च को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई लापता बच्चों के बारे में आशंका है कि उन्हें भीख मंगवाने, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में जबरन लगाया जा सकता है.

आयोग ने कहा कि अगर रिपोर्ट में कही गई बातें सही हैं, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है. आयोग ने यह भी कहा कि राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद लापता लोगों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि बहुत कम लोगों का ही पता चल पा रहा है.

इसी कारण एनएचआरसी ने संबंधित राज्यों से दो हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है, जिसमें यह बताया जाए कि लापता लोगों, खासकर बच्चों, की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की योजना है.

इसके अलावा आयोग ने एनसीआरबी से भी इन पांचों राज्यों में लापता लोगों की स्थिति से जुड़े ताज़ा आंकड़े उसी समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है.

Source: <https://www.livehindustan.com/jharkhand/jamshedpur/story-nhrc-takes-cognizance-of-gurugram-tragedy-7-workers-die-in-stp-collapse-201773421050073.html>

सात श्रमिकों की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा

Mar 13, 2026 10:27 pm IST Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुग्राम में एसटीपी की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से हुई सात श्रमिकों की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने हरियाणा सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। हादसे में घायल मजदूरों के स्वास्थ्य और मुआवजे की जानकारी भी मांगी गई है।

गुरुग्राम/जमशेदपुर, हिटी प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एसटीपी की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से सात श्रमिकों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। शुक्रवार को आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कॉलोनी में सोमवार देर रात निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की खुदाई करने के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई। इस मलबे की चपेट में आने से 11 मजदूर दब गए थे। सात मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों में से छह श्रमिक झारखंड के रहने वाले थे। एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करते हुए कहा है कि यदि खबरें सही हैं तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। आयोग ने यह संकेत दिया है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से निर्दोष मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ठेकेदार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस तरह के हादसों में जान जाना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। इलाज और आर्थिक सहायता की जानकारी मांगी। आयोग ने अपनी नोटिस में स्पष्ट रूप से तीन मुख्य जानकारियां मांगी हैं। हादसे में घायल हुए मजदूरों के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति और उन्हें दिया जा रहा उपचार। अब तक हुई पुलिस और प्रशासनिक जांच का विवरण और दोषियों पर की गई कार्रवाई। मृतक मजदूरों के परिजनों और घायलों को दी गई आर्थिक सहायता या मुआवजे का ब्योरा भी मांगा गया है। आयोग ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 14 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट पेश की जाए। दो लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डर कंपनी, ठेकेदार सहित अन्य छह लोगों के लिए मंगलवार को बिलासपुर थाने में मामला दर्ज किया था। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को गिरफ्तार किया। बुधवार को कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को हादसे में जान गंवाने वाले सात श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 20-20 लाख रुपये के चेक प्रदान किए थे।

Source: <https://www.livehindustan.com/ncr/gurgaon/story-nhrc-takes-cognizance-of-gurugram-tragedy-seven-laborers-die-in-stp-excavation-collapse-201773412596984.html>

श्रमिकों की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा

Mar 13, 2026 08:06 pm IST Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांव

गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। सोमवार देर रात को सिधरावली गांव में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स की कॉलोनी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की

गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एसटीपी की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से सात श्रमिकों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। शुक्रवार को आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स कॉलोनी में सोमवार देर रात निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की खुदाई करने के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई। इस मलबे की चपेट में आने से 11 मजदूर दब गए थे। सात मजदूरों की मौत पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एनएचआरसी

ने मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करते हुए कहा है कि यदि खबरें सही हैं तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। आयोग ने यह संकेत दिया है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से निर्दोष मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ठेकेदार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस तरह के हादसों में जान जाना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। इलाज और आर्थिक सहायता की जानकारी मांगी। आयोग ने अपनी नोटिस में स्पष्ट रूप से तीन मुख्य जानकारियां मांगी हैं। हादसे में घायल हुए मजदूरों के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति और उन्हें दिया जा रहा उपचार। अब तक हुई पुलिस और प्रशासनिक जांच का विवरण और दोषियों पर की गई कार्रवाई। मृतक मजदूरों के परिजनों और घायलों को दी गई आर्थिक सहायता या मुआवजे का ब्योरा भी मांगा गया है। आयोग ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 14 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट पेश की जाए। इस मामले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच की निगरानी अब सीधे मानवाधिकार आयोग कर रहा है। दो लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डर कंपनी, ठेकेदार सहित अन्य छह लोगों के लिए मंगलवार को बिलासपुर थाने में मामला दर्ज किया था। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को गिरफ्तार किया। बुधवार को कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को हादसे में जान गंवाने वाले सात श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 20-20 लाख रुपये के चेक प्रदान किए थे।

Source: <https://www.jagran.com/haryana/gurgaon-nhrc-seeks-report-on-gurugram-soil-collapse-deaths-40170674.html>

गुरुग्राम में मिट्टी धंसने की घटना: मानवाधिकार आयोग ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट, दो गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Rajesh Kumar

Updated: Fri, 13 Mar 2026 08:34 PM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम के सिधरावली में सिग्नेचर ग्लोबल कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए मिट्टी धंसने की घटना का संज्ञान लिया, जिसमें सात मजदूरों की मौत हो गई थी।

HighLights

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम घटना का संज्ञान लिया।

सात मजदूरों की मौत, चार घायल, विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज, दो अधिकारी गिरफ्तार।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को उस घटना का संज्ञान लिया, जिसमें सिधरावली में सिग्नेचर ग्लोबल के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी धंसने से सात मजदूरों की मौत हो गई थी। NHRC ने राज्य के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस मामले पर दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में विशेष रूप से घायल व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति, चल रही जांच, और मृतकों के परिजनों तथा घायलों को दिए गए मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी गई है।

मानवाधिकार आयोग ने इस घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया। इन रिपोर्टों में बताया गया था कि 9 मार्च को गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके के पास सिग्नेचर ग्लोबल के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी धंसने से सात मजदूरों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

आयोग ने पाया कि जिस तरह से यह घटना हुई, उससे पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। इसके परिणामस्वरूप, आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस मामले पर दो हफ्ते के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। यह बताना जरूरी है कि यह घटना सोमवार रात को कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई थी। इस मामले के संबंध में, बिलासपुर पुलिस ने छह व्यक्तियों जिनमें कंपनी के प्रतिनिधि और ठेकेदार शामिल हैं। उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) और सुरक्षा नियमों के पालन में लापरवाही से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।

पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर विकास पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए जांच जारी है।

Source: <https://www.bhaskarhindi.com/other/delhi-nhrc-ne-purvottar-ki-mahilaon-ke-sath-hue-ashobhaniya-vyavhar-par-liya-suo-motu-sangyan-1264321>

दिल्ली एनएचआरसी ने पूर्वोत्तर की महिलाओं के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार पर लिया स्वतः संज्ञान

देश की राजधानी राष्ट्रीय दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में पूर्वोत्तर महिला के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार और मारपीट के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया।

By 3 मार्च 2026

नई दिल्ली, 13 मार्च (आईएनएस)। देश की राजधानी राष्ट्रीय दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में पूर्वोत्तर महिला के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार और मारपीट के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया।

एनएचआरसी ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है, जिसमें कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से पीड़िता के स्वास्थ्य और अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है।

इसके अलावा, आयोग की तरफ से जारी की गई पोस्ट में घटना के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। एनएचआरसी के मुताबिक, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मणिपुर की कुछ महिलाओं पर एक लड़कों का समूह अशोभनीय टिप्पणी कर रहा था, जिसका इन महिलाओं ने विरोध किया और इसके बाद पूरी स्थिति मारपीट में तब्दील हो गई।

वहीं, मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह घटना 10 मार्च की है, जब पीड़िता अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्क में तस्वीरें ले रही थीं, तभी वहां पर मौजूद लड़कों के एक समूह ने उन पर अशोभनीय टिप्पणी की, जिसका उन्होंने विरोध किया।

इससे पहले, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस घटना की निंदा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि भारत में पूर्वोत्तर के लोगों पर बार-बार हो रहे हमलों से मैं बहुत आहत हूं। दिल्ली के साकेत कोर्ट के पास मणिपुर और असम के हमारे दो लोगों पर हुआ शारीरिक हमला बेहद निंदनीय है। नस्लीय उत्पीड़न को सामान्य स्थिति नहीं माना जाना चाहिए और हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे कड़ी कार्रवाई करें।

Source: <https://www.punjabkesari.com/india-news/delhi-nhrc-ne-purvottar-ki-mahilaon-ke-sath-hue-ashobhaniya-vyavhar-par-liya-suo-motu-sangyan/>

दिल्ली: एनएचआरसी ने पूर्वोत्तर की महिलाओं के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार पर लिया स्वतः संज्ञान

04:44 PM Mar 13, 2026 IST | IANS

नई दिल्ली, 13 मार्च (आईएनएस)। देश की राजधानी राष्ट्रीय दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में पूर्वोत्तर महिला के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार और मारपीट के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया।

एनएचआरसी ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है, जिसमें कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से पीड़िता के स्वास्थ्य और अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है।

इसके अलावा, आयोग की तरफ से जारी की गई पोस्ट में घटना के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। एनएचआरसी के मुताबिक, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मणिपुर की कुछ महिलाओं पर एक लड़कों का समूह अशोभनीय टिप्पणी कर रहा था, जिसका इन महिलाओं ने विरोध किया और इसके बाद पूरी स्थिति मारपीट में तब्दील हो गई।

वहीं, मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह घटना 10 मार्च की है, जब पीड़िता अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्क में तस्वीरें ले रही थीं, तभी वहां पर मौजूद लड़कों के एक समूह ने उन पर अशोभनीय टिप्पणी की, जिसका उन्होंने विरोध किया।

इससे पहले, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस घटना की निंदा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि भारत में पूर्वोत्तर के लोगों पर बार-बार हो रहे हमलों से मैं बहुत आहत हूं। दिल्ली के साकेत कोर्ट के पास मणिपुर और असम के हमारे दो लोगों पर हुआ शारीरिक हमला बेहद निंदनीय है। नस्लीय उत्पीड़न को सामान्य स्थिति नहीं माना जाना चाहिए और हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे कड़ी कार्रवाई करें।

--आईएनएस

एमएस/



Tarun Mitra, Online News, 14/03/2026

Source: <https://www.tarunmitra.in/national/nhrc-notice-to-five-states-on-missing-people-and-human/article-131811>

लापता लोगों व मानव तस्करी पर पांच राज्यों को एनएचआरसी का नोटिस

Published By Harshit

On Mar 13, 2026 07:49 PM IST

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या और उन्हें ढूंढने में प्रशासन के निराशाजनक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।



Source: <https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-ranchi-jharkhandphp/cid18360862.htm>

नवजात शिशु की मौत मामले में झारखंड के अधिकारियों को एनएचआरसी का नोटिस

By VocalTV Desk | Mar 13, 2026, 16:32 IST

नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के मामले में अस्पताल कर्मियों की तरफ से की गई लापरवाही का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है।

आयोग ने झारखंड के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस न दिए जाने के बाद पिता को शिशु के शव को गत्ते के बक्से में रख कर बंगरासाई गांव ले जाना पड़ा। खबरों के मुताबिक, अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार को शिशु के शव को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए मजबूर किया और किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी



Source: [VocalTV https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-haryana-govtphp/cid18360467.htm](https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-haryana-govtphp/cid18360467.htm)

श्रमिकों की मौत के मामले में हरियाणा सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

By VocalTV Desk | Mar 13, 2026, 15:26 IST

नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बिलासपुर क्षेत्र के पास एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से सात श्रमिकों की मौत और तीन अन्य के घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने बताया कि 10 मार्च 2026 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 9 मार्च को हरियाणा के गुरुग्राम के बिलासपुर क्षेत्र के पास एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से कम से कम सात श्रमिकों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। कम से कम 10 और श्रमिकों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। यह घटना उस स्थल पर हुई जहां एक आगामी आवासीय परियोजना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा दल, बचावकर्मी, दमकलकर्मी और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों सहित अन्य एजेंसियां मलबे के नीचे फंसे श्रमिकों की तलाश कर रही थीं। आयोग ने रिपोर्ट में घायल व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति और मृतक आश्रितों एवं घायल व्यक्तियों के परिजनों को दिए गए मुआवजे का भी विवरण मांगा है।



Source: <https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-five-state-govtphp/cid18360466.htm>

मानवाधिकार आयोग का लापता व्यक्तियों और मानव तस्करी को लेकर पांच राज्यों को नोटिस

By VocalTV Desk | Mar 13, 2026, 14:56 IST

नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश में लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या और उन्हें ढूंढने में प्रशासन के निराशाजनक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बताया कि 9 मार्च 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि मानव तस्करी के अधिकतम मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। किशोर की तस्करी के मामलों में ओडिशा सबसे आगे है। उसके बाद बिहार है। किशोरियों की तस्करी में राजस्थान में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह संदेह है कि इन बच्चों को भीख मांगने, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में धकेला जाता है। बिहार में 2013 से हर साल दर्ज होने वाले 12-14 हजार गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में से दो-तिहाई को ही बचाया जा सका है। इनमें से कई बच्चे हैं।

आयोग ने रिपोर्ट में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों और एनसीआरबी से इन राज्यों में लापता व्यक्तियों की स्थिति पर नवीनतम सांख्यिकीय आंकड़े भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: <https://smarthabari.com/threads/16829/>

दिल्ली में पूर्वोत्तर महिलाओं से बदसलूकी पर NHRC सख्त, लिया स्वतः संज्ञान; दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट

Thread starter IANS

Start date आज 4:45 PM बजे

आज 4:45 PM बजे

नई दिल्ली, 13 मार्च। देश की राजधानी राष्ट्रीय दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में पूर्वोत्तर महिला के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार और मारपीट के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया।

एनएचआरसी ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है, जिसमें कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से पीड़िता के स्वास्थ्य और अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है।

इसके अलावा, आयोग की तरफ से जारी की गई पोस्ट में घटना के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। एनएचआरसी के मुताबिक, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मणिपुर की कुछ महिलाओं पर एक लड़कों का समूह अशोभनीय टिप्पणी कर रहा था, जिसका इन महिलाओं ने विरोध किया और इसके बाद पूरी स्थिति मारपीट में तब्दील हो गई।

वहीं, मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह घटना 10 मार्च की है, जब पीड़िता अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्क में तस्वीरें ले रही थीं, तभी वहां पर मौजूद लड़कों के एक समूह ने उन पर अशोभनीय टिप्पणी की, जिसका उन्होंने विरोध किया।

इससे पहले, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस घटना की निंदा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि भारत में पूर्वोत्तर के लोगों पर बार-बार हो रहे हमलों से मैं बहुत आहत हूं। दिल्ली के साकेत कोर्ट के पास मणिपुर और असम के हमारे दो लोगों पर हुआ शारीरिक हमला बेहद निंदनीय है। नस्लीय उत्पीड़न को सामान्य स्थिति नहीं माना जाना चाहिए और हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे कड़ी कार्रवाई करें।

Source: <https://www.bhaskarhindi.com/other/uttam-nagar-hatya-mamla-manavadhikar-aayog-ne-liya-sangyan-dm-aur-police-ayukt-ko-notice-1264320>

उत्तम नगर हत्या मामला मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, डीएम और पुलिस आयुक्त को नोटिस

13 Mar 2026 4:45 PM

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई एक युवक की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पश्चिमी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। साथ ही उनसे दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

नई दिल्ली, 13 मार्च (आईएनएस)। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई एक युवक की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पश्चिमी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। साथ ही उनसे दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

यह नोटिस 12 मार्च को जारी किया गया। आयोग के सहायक रजिस्ट्रार (कानून) की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 6 मार्च 2026 को प्राप्त शिकायत को 12 मार्च को आयोग के समक्ष रखा गया था। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद आयोग ने इसे मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन का मामला मानते हुए कार्रवाई करने का निर्णय लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 4 मार्च 2026 को होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 26 वर्षीय एक हिंदू दलित युवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। बताया गया है कि यह घटना होली खेलने के दौरान पानी के छींटे पड़ने से शुरू हुए एक मामूली विवाद के बाद हुई।

शिकायत के अनुसार, होली के दौरान गलती से पानी पड़ने पर दो परिवारों के बीच कहासुनी हो गई थी। बाद में युवक के परिवार की ओर से माफी भी मांग ली गई थी, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद मामला शांत नहीं हुआ। बताया गया है कि उसी दिन बाद में जब युवक अपने दोपहिया वाहन से घर लौट रहा था, तभी करीब 15 से 20 लोगों के समूह ने उस पर हमला कर दिया।

हमलावरों ने कथित तौर पर ईंट, पत्थर और लोहे की रॉड से युवक पर हमला किया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

शिकायतकर्ता ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और उन्हें उचित मुआवजा भी प्रदान किया जाए।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है। आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि देश में सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने की जिम्मेदारी आयोग की है। साथ ही जांच के मामलों में आयोग के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां भी हैं। आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कथित अपराध में शामिल सभी लोगों की पहचान हो और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग ने यह भी कहा है कि चूंकि पीड़ित परिवार के सदस्य इस मामले में अहम गवाह हो सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का आकलन किया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा, आयोग ने निर्देश दिया है कि घटना से जुड़े सभी संभावित सबूतों को सुरक्षित रखा जाए।

आयोग ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े जो भी फोटो या वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। उन्हें भी जांच एजेंसी सुरक्षित करे क्योंकि उनमें फॉरेंसिक या अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं। आयोग ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा कर उसे सुरक्षित रखा जाए, ताकि जांच में मदद मिल सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि घटनास्थल को ठीक तरह से सुरक्षित किया गया हो और वहां से सभी जरूरी फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हों। इनमें उंगलियों के निशान, पैरों के निशान, हमले में इस्तेमाल किए गए पत्थर, ईंट या अन्य वस्तुएं और अन्य भौतिक साक्ष्य शामिल हैं।

आयोग ने कहा है कि इन सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए संरक्षित किया जाए। मानवाधिकार आयोग ने पश्चिमी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस आयुक्त से कहा है कि वे इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर आयोग को भेजें।



Source: <https://www.bhaskarhindi.com/city/mumbai/as-the-number-of-missing-persons-increases-the-nhrc-issues-notices-to-the-chief-secretaries-and-director-generals-of-police-dgprs-of-five-states-including-maharashtra-1264379>

मानव तस्करी: लापता लोगों की संख्या में बढ़ोतरी, एनएचआरसी ने महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी नोटिस

13 Mar 2026 6:28 PM

मानव तस्करी के अधिकतम मामले ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज लापता होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस जारी

New Delhi News राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने लापता होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी और उनका पता लगाने की धीमी रफ्तार पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, ओडिशा और तेलंगाना महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने बिहार में वर्ष 2013 से हर वर्ष 12,000 से 14,000 व्यक्तियों के लापता होने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाया है। लापता व्यक्तियों में से केवल दो-तिहाई बच्चों का ही पता लगाया जा सका है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी के अधिकतम मामले महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और तेलंगाना में दर्ज किए गए हैं।

नाबालिग लड़कों की तस्करी के मामलों में ओडिशा सबसे आगे है और बिहार दूसरे स्थान पर है। नाबालिग लड़कियों की तस्करी के सबसे अधिक मामले राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। आयोग ने एनसीआरबी से इन राज्यों में लापता व्यक्तियों की स्थिति पर नवीनतम आंकड़े दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

9 मार्च 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लापता बच्चों को भीख मांगने, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में धकेले जाने की आशंका है।



Source: <https://www.yugwarta.com/Encyc/2026/3/13/NHRC-NOTICE-RANCHI-JHARKHAND.html>

नवजात शिशु की मौत मामले में झारखंड के अधिकारियों को एनएचआरसी का नोटिस

Yugwarta | 13 Mar 2026

नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के मामले में अस्पताल कर्मियों की तरफ से की गई लापरवाही का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है।

आयोग ने झारखंड के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस न दिए जाने के बाद पिता को शिशु के शव को गत्ते के बक्से में रख कर बंगरासाई गांव ले जाना पड़ा। खबरों के मुताबिक, अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार को शिशु के शव को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए मजबूर किया और किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: <https://haryana.punjabkesari.in/haryana/news/human-rights-commission-issued-notice-to-haryana-govt-and-police-commissioner-2306700>

मिट्टी ढहने से मजदूरों की मौत मामले में हरियाणा सरकार और पुलिस कमिश्नर को मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 13 Mar, 2026 05:54 PM

गांव सिधरावली में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स की कॉलोनी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 7 मजदूरों की मौत व 4 के घायल होने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है।

गुडगांव, (ब्यूरो): गांव सिधरावली में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स की कॉलोनी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 7 मजदूरों की मौत व 4 के घायल होने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और गुडगांव पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सोमवार देर रात को निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की खुदाई करने के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई। इस मलबे की चपेट में आने से सात मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई घंटों तक राहत कार्य चला, जिसमें एनडीआरफ, एसडीआरफ, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला।

मानव अधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करते हुए कहा है कि यदि खबरें सही हैं तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। आयोग ने यह संकेत दिया है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से निर्दोष मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ठेकेदार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस तरह के हादसों में जान जाना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है।

आयोग ने अपनी नोटिस में स्पष्ट रूप से तीन मुख्य जानकारियां मांगी हैं। हादसे में घायल हुए मजदूरों के स्वास्थ्य का वर्तमान स्टेटस और उन्हें दिया जा रहा उपचार। अब तक हुई पुलिस और प्रशासनिक जांच का पूरा विवरण और दोषियों पर की गई कार्रवाई। मृतक मजदूरों के परिजनों और घायलों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता या मुआवजे का ब्यौरा मांगा गया है। आयोग ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 14 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट पेश की जाए। इस मामले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच की निगरानी अब सीधे मानवाधिकार आयोग कर रहा है।

हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डर कंपनी, ठेकेदार सहित अन्य छह लोगों को मंगलवार को बिलासपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले में जांच करते हुए मंगलवार को पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जबकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुधवार को हादसे में जान गंवाने वाले सात श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 20-20 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए थे।



Source: <https://www.univarta.com/news/india/story/3772590.html>

प्रसव चिकित्सा देखभाल सही ढंग मुहैया नहीं कराने को लेकर एनएचआरसी ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब

Uniindia News Service

भारत Posted at: Mar 13 2026 2:16PM

नयी दिल्ली 13 मार्च (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर चिकित्सा देखभाल सही ढंग से नहीं मिलने के कारण नवजात शिशु की मृत्यु की खबर का स्वतः संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य के चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के सचिव तथा पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त से दो सप्ताह में जबाब मांगा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत सात मार्च को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस की सुविधा न दिए जाने पर पिता को शिशु के शव को गत्ते के बक्से में रखकर बंगरासाई गांव ले जाना पड़ा था।

विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवाएं लें।



Source: <https://dainikbharat24.com/nhrc-notice-to-health-secretary-and-deputy-commissioner-of-west-singhbhum/>

एनएचआरसी का स्वास्थ्य सचिव और पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को नोटिस

13/03/2026 dainikbharat24

एनएचआरसी का स्वास्थ्य सचिव और पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को नोटिस

दो सप्ताह के भीतर नवजात शिशु की मौत पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वास्थ्य सचिव और पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को नोटिस जारी किया है। उनसे पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में हुई नवजात शिशु की मौत पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में सही ढंग से प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर चिकित्सा देखभाल न मिलने के कारण नवजात शिशु की मृत्यु की खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। खबरों के अनुसार, 7 मार्च, 2026 को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिए जाने पर पिता को शिशु के शव को गत्ते के बक्से में रखकर बंगरासाई गांव ले जाना पड़ा था।

आयोग ने पाया है कि अगर इस खबर में दी गई जानकारी सही है, तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। इसलिए, आयोग ने रांची स्थित स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार को मृत शिशु के शव को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए मजबूर किया। किसी भी प्रकार की सहायता देने से भी इनकार कर दिया।